घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com **अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 234- गुरूवार 25- जून 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये** RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

मोदी ने कैबिनेट मीटिंग में री-नीट एग्जाम की तारीफ की...

कहा...मंत्रालयों के बीच बेहतर तालमेल हर चुनौती से निपटने की गारंटी...

नई दिल्ली,24 जून 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में नीट-यूजी री-एग्जाम के सुचारू संचालन के लिए प्रयासों की तारीफ की। सूत्रों के हवाले से किया है। इस दौरान मोदी ने विभिन्न विभागों के बीच तालमेल पर भी जोर दिया। मीटिंग से एक दिन पहले दो हलचल देखने को मिली थीं। दरअसल मंगलवार को केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उनका राज्यसभा कार्यकाल खत्म हो गया था और भाजपा ने उन्हें दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा। कुरियन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसी बीच शाम को राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार समारोह के बाद पीएम ने राष्ट्रपति

से मुलाकात की। ऐसे में चर्चा चल रही थी कि केंद्र सरकार जल्द ही कैबिनेट में फेरबदल कर सकती है। हालांकि अभी इसे लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

दो मंत्रियों को दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा गया : भाजपा ने हालिया राज्यसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह बिट्टू को दोबारा उम्मीदवार नहीं बनाया। जॉर्ज कुरियन का राज्यसभा कार्यकाल 21 जून को समाप्त हुआ और उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया। रवनीत सिंह बिट्टू का कार्यकाल भी खत्म हो गया है, लेकिन उन्होंने अभी इस्तीफा नहीं दिया है। नियमों के अनुसार बिट्टू छह महीने तक सांसद बने बिना मंत्री रह सकते हैं। रवनीत सिंह बिट्टू ने संकेत दिए हैं कि वह पंजाब की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में वह चुनाव लड़ सकते हैं और पंजाब में काम करना चाहते हैं।

एक व्यक्ति-एक पद' फॉर्मूले का असर : भाजपा के भीतर 'वन मैन, वन पोस्ट' सिद्धांत भी फेरबदल की वजह माना जा रहा है। हर्ष मल्होत्रा को हाल ही में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि वे केंद्र में मंत्री भी हैं।

पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हैं और वित्त राज्य मंत्री भी। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि संगठनात्मक जिम्मेदारी मिलने के बाद इन नेताओं को मंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है।

स्वस्थ भारत ही विकसित भारत की आधारशिला

2047 तक विकसित राष्ट्र बनना साझा लक्ष्य : नड्डा

देहरादून,24 जून 2026। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने बुधवार को कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य अब पूरे देश का साझा संकल्प बन चुका है। आज हर नागरिक के सामने एक सामान्य लक्ष्य है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने। देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि 'सेहत अच्छी होगी तो आर्थिक विकास होगा,क्योंकि इससे उत्पादकता बढ़ेगी। इसलिए स्वास्थ्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना समय की आवश्यकता है।' उन्होंने कहा कि देश के आर्थिक विकास की नींव बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था पर टिकी है और स्वस्थ नागरिक ही विकसित भारत के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब देश में 'हम कर सकते हैं और हम करेंगे' की भावना विकसित हुई है, जिसने विकास और सुशासन को नई दिशा दी है। केंद्रीय मंत्री ने देश की राजनीतिक और सामाजिक सोच में आए बदलाव का उल्लेख करते हुए कहा कि एक समय ऐसा था जब आम नागरिकों ने यह मान लिया था कि व्यवस्था में कोई बदलाव संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि लगभग 12-13 वर्ष पहले लोगों के मन में यह धारणा घर कर गई थी कि परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, लेकिन पिछले एक दशक में देश की राजनीतिक

सोच में व्यापक परिवर्तन आया है। उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में केंद्र सरकार की नीतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2017 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के मूल ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। उन्होंने कहा कि पहले स्वास्थ्य सेवाओं का फोकस केवल बीमारी के इलाज तक सीमित था, जबकि वर्तमान सरकार ने उपचार आधारित व्यवस्था के साथ-साथ रोकथाम आधारित स्वास्थ्य प्रणाली को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि अब स्वास्थ्य क्षेत्र में लोगों को बीमार होने के बाद उपचार उपलब्ध कराने के बजाय बीमारियों की रोकथाम,जागरूकता और समय रहते हस्तक्षेप पर जोर दिया जा रहा है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य अवसंरचना के विस्तार का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि एम्स ऋषिकेश स्वास्थ्य क्षेत्र में अग्रणी संस्थान के रूप में उभरा है।

संक्षिप्त समाचार

सांसदों के बाद उद्धव की शिवसेना पर नई आफत,छिन सकता है संसद में मिला दफ्तर

मुंबई,24 जून 2026। लोकसभा सांसदों की बगावत के झटके से उबर रही शिवसेना (उद्धव) को एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है। सांसदों की संख्या में कमी के बाद अब संसद भवन परिसर में पार्टी को मिले कार्यालय पर खतरा मंडरा रहा है।

बागी सांसदों के औपचारिक विलय के बाद शिवसेना (उद्धव) के पास सिर्फ 4 सांसद ही बचेंगे। ऐसे में अब संसद भवन परिसर में पार्टी के कार्यालय के आवंटन पर संकट मंडराने लगा है। संसदीय नियमों के तहत, संसद भवन परिसर के भीतर अलग कार्यालय आमतौर पर केवल 5 या इससे ज्यादा सांसदों वाली पार्टियों को ही आवंटित किया जाता है। उद्धव की शिवसेना के पास अब 4 ही सांसद रह जाएंगे, ऐसे में आशंका है कि उसे आवंटित किया गया कार्यालय वापस लिया जा सकता है। पार्टी के संसदीय दल का कार्यालय फिलहाल पुराने संसद भवन भवन के संविधान सदन के कमरा नंबर 128ए से संचालित होता है। सांसदों की बगावत के बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उद्धव की शिवसेना को बैठक के लिए बुलाया है। ठाकरे गुट का कहना है कि बागी सांसदों को अलग गुट के तौर पर मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। दोनों नेता स्पीकर से अनुरोध करेंगे कि पार्टी की आधिकारिक पहचान और अधिकार उद्धव गुट के पास ही रहें।

गुजरात के राजकोट में फांसी से लटकी मिलीं आप नेता,लिव-इन पार्टनर पर हत्या का शक...

राजकोट,24 जून 2026। गुजरात के राजकोट में एक 23 वर्षीय युवती का शव उनके फ्लैट में मिलने से सनसनी फैल गई है। उनकी पहचान नंदनी आनंदभाई बोसमिया के रूप में हुई है, जो आम आदमी पार्टी (आप)

की नेता थीं। रिपोर्ट के मुताबिक, नंदिनी का शव राजकोट के गोंडल चौकड़ी के पास आगमन सिटी स्थित उनके फ्लैट में फांसी से लटका मिला है। नंदिनी यहां लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थीं। उनके परिवार ने प्रेमी पर हत्या का आरोप लगाया है। परिवार के लोगों ने बताया कि वह नंदिनी को संपर्क कर रहे थे, लेकिन फोन का जवाब न मिलने पर उन्होंने फ्लैट पर जाकर चेक किया। नंदिनी के पिता आनंदभाई बोस्मिया ने बताया कि उनकी बेटी का फ्लैट पांचवीं मंजिल पर था, जहां जाने पर फ्लैट के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। नंदिनी जेतपुर में आप के टिकट पर नगर पालिका का चुनाव लड़ चुकी हैं। वह मेडिकल प्रतिनिधि थी। नंदिनी के परिजनों ने बताया कि नंदिनी जूनागढ़ में असलम हुसैन समा के किराए के मकान में रहती थीं, जहां उसका असलम से संपर्क बढ़ा और दोनों प्यार करने लगे।

ईरान ने प्रधानमंत्री मोदी को अयातुल्लाह अली खामेनेई के राजकीय अंतिम संस्कार में बुलाया

तेहरान,24 जून 2026। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने अपने दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के राजकीय

अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को औपचारिक न्यौता दिया है। यह कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में आयोजित होगा, जिसमें वैश्विक प्रतिनिधिमंडलों के शामिल होने की उम्मीद है। ईरान ने अफगानिस्तान में तालिबानी प्रधानमंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को भी बुलाया है। रिपोर्ट के मुताबिक, अभी भारत ने न्यौते पर कोई जानकारी नहीं दी है। अमेरिका-इजरायल के साथ युद्धविराम के बाद यह ईरान का पहला औपचारिक कार्यक्रम है। संघर्ष के कारण अली खामेनेई का औपचारिक अंतिम संस्कार लंबित था। यह 4 जुलाई को तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला परिसर में पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन से शुरू होगा।

पुणे हत्याकांड में बड़ा खुलासा: सिया गोयल ने शादी और हत्या की साजिश कबूली...

पुणे,24 जून 2026। पुणे के लोहागढ़ किले में ट्रेकिंग के दौरान हुई 26 वर्षीय केतन अग्रवाल की मौत ने पूरे राज्य को स्तब्ध कर दिया है। शुरुआत में इसे एक साधारण दुर्घटना माना जा रहा था, लेकिन पुलिस की गहन जांच ने इस मामले में एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा किया जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। केतन की मंगेतर सिया गोयल (20) और उसके प्रेमी चेतन चौधरी (22) ने मिलकर केतन को अपने रास्ते से हटाने के लिए एक खौफनाक साजिश रची थी। 18 जून को हुई इस वारदात ने साबित कर दिया कि भरोसे के रिश्ते में छिपी नफरत किस हद तक घातक हो सकती है।

शादी से बचने के लिए प्रेमी के साथ मिलकर बुना जाल : पुलिस जांच में पता चला कि केतन की मंगेतर सिया गोयल इस शादी के बंधन में बंधना नहीं चाहती थी। केतन को अपने रास्ते का कांटा मानकर उसने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर उसे खत्म करने की योजना बनाई। पुणे के कोंढवा इलाके के रहने वाले चेतन और सिया ने इस हत्या को 'दुर्घटना' का रूप देने का पूरा ताना-बाना बुना था। सगाई के बाद से ही सिया का व्यवहार बदलने लगा था और वह लगातार केतन पर लोहागढ़ किले चलने का दबाव बना रही थी। केतन की बहन संजना के अनुसार, सिया पिछले 15 दिनों में केतन को 4 बार उस किले पर ले जाने की कोशिश कर चुकी थी।

सीसीटीवी फुटेज ने खोले कातिलों के चेहरे

इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में लोहागढ़ किले के टिकट काउंटर पर लगे सीसीटीवी फुटेज ने निर्णायक भूमिका निभाई। पुलिस ने जब फुटेज की बारीकी से जांच की, तो उन्हें केतन और सिया के पीछे एक संदिग्ध युवक की गतिविधियां दिखाई दीं। इस फुटेज ने पूरी कहानी पलट दी। पुलिस को पता चला कि केतन को खाई में धकेलने के समय चेतन वहां पहले से ही घात लगाकर बैठा था। इस फुटेज के आधार पर ही पुलिस ने आरोपियों तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

भीषण गर्मी में हुडी पहनने की गलती पड़ी भारी : हत्यारों की चतुराई उस वक्त धरी की धरी रह गई जब सीसीटीवी में उनकी एक छोटी सी चूक सामने आई। वारदात के दिन तापमान लगभग 33 डिग्री सेल्सियस था। इतनी भीषण गर्मी के बावजूद संदिग्ध युवक ने शॉर्ट्स के साथ एक मोटी हुडी पहन रखी थी। उसने हुडी की कैप से अपना चेहरा छुपाया हुआ था और कानों पर हेडफोन लगाए थे। पुलिस को यह पहनावा काफी संदिग्ध लगा। इसके अलावा, एक अन्य फुटेज में दिखा कि जैसे ही सिया ने पीछे मुड़कर देखा, हुडी पहने युवक ने तुरंत नीचे बैठने की कोशिश की, जिससे पुलिस का शक पुख्ता हो गया। पुणे ग्रामीण के एसपी संदीप सिंह गिल ने बताया कि उनकी टीम ने केतन के व्यक्तिगत रिश्तों, मोबाइल रिकॉर्ड और पैसों के लेनदेन जैसे सभी पहलुओं की गहराई से जांच की। पुलिस द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर सिया और चेतन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।

लखनऊ अग्निकांड के बाद बड़ा एक्शन

अब बेसमेंट में नहीं चलेंगी कोचिंग सीएम योगी के सख्त निर्देश...

लखनऊ,24 जून 2026। राजधानी लखनऊ में कोचिंग सेंटर में हुए भीषण अग्निकांड के बाद पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। इस दर्दनाक हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, जिनमें अधिकतर 20 से 30 वर्ष की उम्र के छात्र शामिल थे। घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशभर के कोचिंग संस्थानों और व्यावसायिक भवनों को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं।

बेसमेंट में कोचिंग और कमर्शियल गतिविधियों पर पूरी रोक

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट आदेश दिया है कि अब किसी भी इमारत के बेसमेंट में कोचिंग संस्थान नहीं चलाए जा सकेंगे। इसके साथ ही बेसमेंट में किसी भी प्रकार की कमर्शियल एक्टिविटी या व्यापारिक गतिविधि की अनुमति भी नहीं होगी। यह फैसला हादसे के बाद सुरक्षा मानकों को मजबूत करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है।

कोचिंग संस्थानों के रजिस्ट्रेशन पर सख्ती : सरकार ने प्रदेशभर में सभी कोचिंग संस्थानों के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन पर जोर दिया है। अधिकारियों को निर्देश

दिए गए हैं कि बिना पंजीकरण चल रहे कोचिंग सेंटरों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

फायर सेफ्टी ऑडिट मिशन मोड पर होगा : योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिया कि पूरे प्रदेश में मिशन मोड पर फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि हर जिले में फायर सेफ्टी की गहन जांच होनी चाहिए और सभी सार्वजनिक एवं व्यावसायिक भवनों में सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

अस्पतालों और कॉमर्शियल भवनों की भी जांच : सीएम ने यह भी आदेश दिया है कि अस्पतालों, नर्सिंग होम, मेडिकल कॉलेजों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अन्य व्यावसायिक संस्थानों में भी अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की कड़ाई से जांच की जाए।

कोलकाता के तारातला में निर्माणाधीन गोदान की छत गिरने से कई मजदूर दबे,5 की मौत

कोलकाता,24 जून 2026। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बुधवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां तारातला के पास बन रहे एक गोदाम की छत अचानक ढह गई, जिसमें कई मजदूर दब गए। घटना दोपहर करीब 1:30 बजे ब्रेस ब्रिज रेलवे स्टेशन के पास ऑक्टेवियस टी एंड इंडस्ट्रीज के गोदाम में हुई है। हादसे के समय यहां 35 से 40 मजदूर काम कर रहे थे। अभी तक 5 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है।

सूत्रों ने स्थानीय लोगों के हवाले से बताया कि लोहे और सीमेंट से बनी 3 मंजिला गोदाम का निर्माण लगभग एक साल से चल रहा था। इसमें मरम्मत का काम भी जारी था। बुधवार सुबह गोदाम की तीसरी मंजिल धराशायी हुई, जिसके बाद पूरा गोदाम ढह गया और मजदूर मलबे में दब गए। जिससे कई मंजिलें ढह गईं और मजदूर मलबे के नीचे दब गए। तारातला पुलिस थाने की टीम और दमकल कर्मी मौके पर मौजूद हैं। मौके पर सेना के जवानों को भी मदद के लिए बुलाया गया है। बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल मौके पर पहुंच गई हैं। मलबे में मोटे-मोटे और भारी लोहे के बीम और गार्डर होने के साथ ही कंक्रीट भी है। लोहे और स्टील का बीम काटने के लिए उपकरण का इस्तेमाल हो रहा है। मलबा हटाने के लिए बुलडोजर और मशीन बुलवाई गई है। मृतकों की संख्या बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।

अरुणाचल में भारी बारिश से आई बाढ़ ने मचाई तबाही,डूबे कई गांव,हाईवे पुल बहा

ईटानगर,24 जून 2026। अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश से भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है। राज्य के निचले सुबनसिरी और केयी पन्योर जिलों में तेज बारिश के कारण कई गांव पानी में डूब गए हैं। घरों और फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बह गया। मुख्य हाईवे पुल बह गया है। मौसम विभाग के अनुसार, केवल 3 घंटे (सुबह 6 से 9 बजे) के भीतर ही बहुत तेज बारिश हुई, जिससे नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ गया और बाढ़ जैसे हालात बन गए। अचानक हुई इस भारी बारिश के कारण लुक्सिन गांव और तोरू सर्कल के अंतर्गत आने वाले यियी-1 और यियी-2 गांवों में बाढ़ आ गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह 6:30 बजे के तुरंत बाद बाढ़ का पानी घरों में घुस गया और खेतों में फैल गया। शुरुआती नुकसान के आकलन से पता चलता है कि लुक्सिन गांव में दुखुम आदि का घर और कई अन्य इमारतें

क्षतिग्रस्त हो गईं। अनानास, केले और संतरे के बागानों सहित खड़ी बागवानी और कृषि फसलें भी प्रभावित हुईं। अधिकारियों ने कहा कि विस्तृत रिपोर्ट अभी तैयार की जा रही है। यियी गांव सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक था, जहां बाढ़ का पानी बस्ती के बड़े हिस्से में भर गया। स्थानीय लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर आस-पास के घरों में पहुंचाया गया। अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बाढ़ का असर गांवों से आगे तक फैल गया। भारी बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण केयी पैन्योर जिले के याज़ाली में पोसा स्थित नीपको कॉलोनी में भारी तबाही हुई। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार,15 रिहायशी क्वार्टर नष्ट हो गए और एक मुख्य हाईवे पुल बह गया, जिससे इलाके में संपर्क टूट गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह अचानक आई बाढ़ कई दिनों तक लगातार बारिश के बजाय बादल फटने जैसी तेज़ बारिश के कारण आई। जब कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, खासकर पूर्वी हिमालय के ऊबड़-खाबड़ इलाकों में, तो पानी तेज़ी से पहाड़ों की ढलानों से बहकर नालों और नदियों में चला जाता है। पानी के इस अचानक बहाव से अचानक बाढ़ आ सकती है, भले ही कुल दैनिक बारिश बहुत ज़्यादा न हो। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी दी है कि पानी से संतृप्त मिट्टी, उफान पर बहती नदियां और लगातार मानसून की गतिविधि के कारण आने वाले दिनों में अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बना रह सकता है।

कान्हा टाइगर रिजर्व में केनाइन डिस्टेम्पर वायरस

वायरस का कहर, 7 बाघों की मौत से हड़कंप

मध्य प्रदेश,24 जून 2026। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध कान्हा टाइगर रिजर्व पर इन दिनों एक बड़े और जानलेवा वायरस का साया मंडरा रहा है। इस बाघ अभयारण्य में केनाइन डिस्टेम्पर वायरस का प्रकोप लगातार विकराल रूप धारण कर रहा है, जिसने वन्यजीव प्रेमियों और वन विभाग की नींद उड़ा दी है। हाल ही में इस खतरनाक संक्रमण की चपेट में आकर एक और बाघ की दर्दनाक मौत हो गई है। मुक्की स्थित क्वॉरेंटाइन सेंटर में बाघ का सघन उपचार चल रहा था, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। इस नवीनतम घटना के साथ ही, पिछले लगभग दो महीनों के

भीतर कान्हा टाइगर रिजर्व में इस घातक बीमारी से जान गंवाने वाले बाघों का आंकड़ा बढ़कर सात तक पहुंच गया है, जो एक बेहद चिंताजनक स्थिति की ओर इशारा कर रहा है। वन विभाग से प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार, 4 जून 2026 को कान्हा टाइगर रिजर्व के किसली परिक्षेत्र के अंतर्गत कक्ष क्रमांक 777 में संदूक खोल इलाके में एक बाघ बेहद कमजोर, लाचार और बीमार अवस्था में देखा गया था। नियमित गश्त पर निकले हाथी दल ने तुरंत इस गंभीर स्थिति की सूचना वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को दी। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम लाव-लश्कर के साथ मौके पर पहुंची और सुरक्षित तरीके से बाघ को रेस्क्यू कर मुक्की के क्वॉरेंटाइन सेंटर में शिफ्ट किया। रेस्क्यू किए गए बाघ की जब प्राथमिक स्वास्थ्य जांच की गई, तो उसमें स्पष्ट रूप से केनाइन डिस्टेम्पर वायरस के गंभीर लक्षण दिखाई दिए। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए वन विभाग ने तुरंत शीर्ष वन्यजीव स्वास्थ्य विशेषज्ञों को बुलवाया।

देश में एक जुलाई से वीबी-जी राम जी अधिनियम होगा लागू

नई दिल्ली, 24 जून 2026। केंद्र सरकार आगामी 01 जुलाई 2026 से विकसित भारत- रोज़गार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम- 2025 यानी (वीबी-जी राम जी अधिनियम) लागू करने जा रही है। यह अधिनियम हर वित्त वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम 125 दिनों के रोज़गार की वैधानिक गारंटी प्रदान करता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक इसके तहत गांवों के विकास के लिए अलग-अलग मंत्रालयों और सरकारी योजनाओं को एक साथ जोड़कर काम किया जाएगा।

राम मंदिर चढ़ावा विवाद : सिंधी समाज का 200 किलो चांदी दान विवाद,चंपत राय पर उठे गंभीर सवाल

अयोध्या,24 जून 2026। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे और दान में कथित अनियमितताओं के मामले ने अब एक नया और गंभीर मोड़ ले लिया है। कैसल ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, डॉ. राजू वी. मनवानी ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर सीधा निशाना साधा है। डॉ. मनवानी के अनुसार, 26 जनवरी 2021 को सिंधी समुदाय की ओर से राम मंदिर निर्माण हेतु एक-एक किलोग्राम वजन की 200 चांदी की ईंटें ट्रस्ट को सौंपी गई थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि दान देते समय उन्हें कोई रसीद नहीं दी गई थी। उस समय उन्हें यह आश्वासन

दिया गया था कि ट्रस्ट जांच के बाद तय करेगा कि इन ईंटों का उपयोग कैसे और कहाँ करना है। समय बीतने के साथ और मंदिर ट्रस्ट पर लग रहे हेराफेरी के आरोपों के बाद, डॉ. मनवानी और सिंधी समुदाय में गहरी चिंता व्याप्त है। डॉ. मनवानी ने सार्वजनिक रूप से सवाल उठाया है कि क्या उनकी द्वारा दी गई बेशकीमती चांदी किसी गलत जगह या अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की गई है?

संपादकीय

आस्था पर आघात है चढ़ावा चोरी

सदियों के संघर्ष,असंख्य लोगों के बलिदान और दशकों की कानूनी लड़ाई के बाद अयोध्या में साकार हुए राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी के मामले ने लोगों की आस्था पर गहरी चोट करने के साथ ही उनके भरोसे को डिगाने का काम किया है। किसी के लिए भी यह सोचना कठिन है कि चढ़ावे में चोरी वही लोग कर रहे थे,जिन पर उसकी पाई-पाई का हिसाब रखने की जिम्मेदारी थी। इस हैरान-परेशान करने वाले मामले की जांच एसआइटी की ओर से की जा रही है। आशा की जाती है कि सच में दूध का दूध और पानी का पानी होगा, लेकिन तब तक ऐसा हो न जाए, तब तक निश्चित नहीं हुआ जा सकता।

कहना कठिन है कि चढ़ावे में चोरी कब से हो रही थी, लेकिन यह विचित्र है कि सबसे पहले इसकी भनक स्थानीय विपक्षी नेताओं को लगी और फिर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे सार्वजनिक किया। जब ऐसा हुआ तो मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सब कुछ ठीक होने का दावा कर दान राशि में किसी तरह की हेराफेरी से इन्कार कर दिया। आखिर उन्हें ऐसा करने की जल्दी क्या थी? इस इन्कार के बाद यह सामने आया कि कुछ लोगों के ठिकानों से पैसा मिला। यह भी पता चला कि जो लोग दान राशि की गिनती में शामिल थे,उनकी आर्थिक हैसियत अचानक अच्छी हो गई थी और वे लाखों-करोड़ों की जमीन खरीद रहे थे। ऐसी बातें भी सामने आई कि जिन लोगों ने भगवान राम को आभूषण आदि अर्पित किए,उन्हें दान की रसीद नहीं दी गई और कुछ से यह कहा गया कि उन्होंने भेंट स्वरूप चांदी या सोने का जो कुछ दिया था, उसे गला दिया गया है। यह भी सामने आया कि दान पात्रों की निगरानी और दान राशि की गणना भी सही तरह नहीं हो रही थी। जब कथित आंतरिक जांच में गंभीर किस्म की गड़बड़ी सामने आई तो मंदिर ट्रस्ट की ओर से राज्य सरकार से जांच कराने को कहा गया। इसके बाद एसआइटी का गठन हुआ। इसके पहले राम मंदिर प्रबंधन समिति के जो अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र यह कह रहे थे कि उनका काम केवल निर्माण कार्यों को देखना है, वे अचानक टीवी चैनलों में यह बताते हुए दिखाई दिए कि दान पात्रों की निगरानी और चौकसी में भारी कमी थी। उन्होंने चढ़ावा चोरी को डकैती कह कर स्वतः ही मामले की गंभीरता को रेखांकित कर दिया। उन्होंने इसकी भी जरूरत जतानी शुरू कर दी कि मंदिर प्रबंधन की देख-रेख के लिए किसी सीईओ की नियुक्ति आवश्यक है। आखिर इसकी आवश्यकता पहले क्यों नहीं महसूस की गई? वास्तव में ऐसे एक नहीं अनेक सवाल हैं। समझना कठिन है कि ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी मंदिर की व्यवस्था के संचालन में सक्रिय क्यों नहीं थे? ऐसा क्यों लगता है कि कुछ सदस्य केवल नाममात्र के सदस्य थे? क्या ऐसा इसलिए था कि कुछ लोगों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था? सच जो भी हो, यह विचित्र है कि करोड़ों लोगों की आस्था पर आघात पहुंचाने वाले इस मामले के सामने आने के बाद किसी ने भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेने का साहस नहीं दिखाया। किसी ने भी जांच होने तक ही सही,अपना पद छोड़ने की पेशकश भी नहीं की।

इतने विख्यात और प्रतिष्ठित मंदिर के ट्रस्ट के पदाधिकारियों को नैतिकता का परिचय देने के लिए तत्पर रहना चाहिए था। राम मंदिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर है। इस मंदिर के व्यवस्थापकों को तो उच्च स्तर की मर्यादा दिखानी चाहिए थी। क्या वे तभी अपना पद छोड़ेंगे,जब एसआइटी उनकी भूमिका संदिग्ध करार देगी या फिर वे पुलिस जांच में गुनहगार दिखने लगेंगे? इस मामले में अभी तक कोई एफआइआर दर्ज न होना भी कई सवाल खड़े कर रहा है। जब मामले की तह तक पहुंचने के लिए देर-सबेर यह काम करना ही होगा, तो फिर इसमें देरी का क्या औचित्य? यह ऐसा मामला नहीं कि चढ़ावे के हिसाब-किताब और उसकी देखरेख संबंधी कमियों को ठीक कर देने से कर्तव्य की इतिश्री हो जाएगी। जिन लोगों ने चढ़ावा चोरी का पाप किया है, उन्हें कठोर दंड का भागीदार बनाए और जिनकी लापरवाही से ऐसा हुआ,उन्हें व्यवस्था से बाहर किए बिना भरोसे की बहाली होने वाली नहीं है। भरोसे की बहाली के लिए जो कुछ भी संभव है, किया जाना चाहिए। आवश्यक हो तो राम मंदिर ट्रस्ट को भंग किया जाए और उसे नए सिरे से गठित किया जाए, क्योंकि मामला करोड़ों रुपये की हेराफेरी का ही नहीं, करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का भी है।

लखनऊ कोचिंग अग्निकांड : क्या हमारे बच्चों की सुरक्षा सिर्फ खबर बनकर रह जाएगी?

डॉ.सत्यवान सौरभ
भिवानी,हरियाणा

लखनऊ में हुए हालिया कोचिंग अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। धुएँ से घिरी इमारतें,चीखते-बिलखते विद्यार्थी, घबराए हुए अभिभावक और राहत-बचाव दलों की भागदौड़—ये दृश्य केवल एक दुर्घटना की तस्वीर नहीं हैं,बल्कि हमारी व्यवस्था की उन कमजोरियों का आईना हैं जिन्हें हम वर्षों से अनदेखा करते आ रहे हैं। हर बार किसी बड़े हादसे के बाद कुछ दिनों तक शोक,संवेदना और आक्रोश दिखाई देता है,फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारे बच्चों की सुरक्षा केवल कुछ दिनों की खबर बनकर रह जाएगी? क्या हम तब तक जागेंगे नहीं,जब तक अगली त्रासदी किसी और शहर में,किसी और कोचिंग संस्थान या हॉस्टल में घटित नहीं हो जाती?

आज भारत में लाखों विद्यार्थी अपने घरों से दूर रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। कोटा,दिल्ली,लखनऊ, प्रयागराज,पटना,जयपुर और चंडीगढ़ जैसे शहर शिक्षा के बड़े केंद्र बन चुके हैं। अभिभावक अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए बड़ी उम्मीदों के साथ उन्हें इन संस्थानों में भेजते हैं। वे फीस भरते हैं, हॉस्टल का खर्च उठाते हैं और यह भरोसा करते हैं कि जहां उनका बच्चा पढ़ रहा है, वहां उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। दुर्भाग्य से यह भरोसा कई बार टूट जाता है।

ऐसे हादसे अचानक नहीं होते। इनके पीछे वर्षों की लापरवाही,नियमों की अनदेखी और जवाबदेही की कमी होती है। जब किसी इमारत में पर्याप्त आपातकालीन निकास नहीं होते,जब बिजली की वायरिंग मानकों के अनुरूप नहीं होती,जब फायर एक्सटिंग्विशर केवल दिखावे के लिए लगाए जाते हैं, जब भवन निर्माण नियमों को ताक पर रखकर व्यावसायिक गतिविधियां चलाई जाती हैं, तब किसी भी दिन एक छोटी-सी चिंगारी बड़ी त्रासदी का रूप ले सकती है।

इस घटना के बाद सबसे पहला प्रश्न अभिभावकों को स्वयं से पूछना चाहिए कि क्या उन्होंने कभी अपने बच्चे के कोचिंग संस्थान,हॉस्टल या पीजी की सुरक्षा व्यवस्था की वास्तविक जांच की है? अक्सर हम संस्थान की प्रतिष्ठा, परिणाम और सुविधाओं के बारे में पूछते हैं, लेकिन सुरक्षा संबंधी प्रश्नों को नजरअंदाज कर देते हैं। यह प्रवृत्ति बदलनी होगी। बच्चे के भविष्य जितना महत्वपूर्ण है,उसका जीवन और सुरक्षा उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

अभिभावकों को सबसे पहले आपात कालीन निकास की स्थिति की जांच करनी चाहिए। किसी भी भवन में आग लगने की स्थिति में सुरक्षित निकास जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर साबित हो सकता है। कई संस्थानों में आपातकालीन सीढ़ियां या तो बंद रहती हैं या उनमें सामान भरा रहता है। कुछ जगहों पर सुरक्षा द्वारों पर ताले लगे होते हैं। ऐसी स्थिति में भगदड़ और अफरा-तफरी के दौरान बाहर निकलना लगभग असंभव हो जाता है। यदि किसी भवन में आपातकालीन निकास स्पष्ट रूप से चिन्हित नहीं हैं या उनके उपयोग में कोई बाधा है,तो उसे गंभीर चेतावनी समझना चाहिए।

दूसरा महत्वपूर्ण पहलू अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता और कार्यशीलता है। फायर एक्सटिंग्विशर केवल दीवारों पर टांग देने से सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती। उनकी नियमित जांच, रखरखाव और समय-समय पर रिफिलिंग आवश्यक है। अभिभावकों को यह जानने का अधिकार है कि संस्थान में कितने अग्निशमन यंत्र हैं, उनकी वैधता क्या है और क्या स्टाफ को उनके उपयोग का प्रशिक्षण दिया गया है। यदि कोई संस्थान इन सवालों के स्पष्ट उत्तर नहीं देता, तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर संदेह होना चाहिए।

तीसरा मुद्दा फायर एनओसी यानी अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाणपत्र का है। हमारे देश में अक्सर देखा गया है कि कागजों पर सभी नियम पूरे दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति अलग होती है। कई बार निरीक्षण केवल औपचारिकता बनकर रह जाता है। इसलिए केवल एनओसी की प्रति देखना पर्याप्त नहीं है। उसकी वैधता,निरीक्षण रिपोर्ट और सुरक्षा मानकों की वास्तविक स्थिति की भी जांच आवश्यक है। प्रशासन को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि फायर एनओसी केवल कागजी प्रक्रिया न रह जाए, बल्कि वास्तविक सुरक्षा का प्रमाण बने।

इमारत की संरचना भी सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कई कोचिंग संस्थान संकरी गलियों में स्थित बहुमंजिला इमारतों में संचालित होते हैं। इनमें पर्याप्त वेंटिलेशन नहीं होता, खिड़कियां सीमित होती हैं और भीड़ क्षमता से कहीं अधिक होती है। ऐसी इमारतें दुर्घटना की स्थिति में मौत के जाल में बदल सकती हैं। इसलिए भवन निर्माण मानकों का पालन सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है।

सुरक्षा केवल उपकरणों से नहीं आती, बल्कि तैयारी से भी आती है। क्या संस्थान नियमित फायर ड्रिल आयोजित करता है? क्या विद्यार्थियों को बताया जाता है कि आपातकाल की स्थिति में क्या करना है? क्या स्टाफ को प्राथमिक आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया है? इन प्रश्नों के उत्तर अक्सर नकारात्मक होते हैं। जबकि विकसित देशों में स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में नियमित सुरक्षा अभ्यास अनिवार्य होता है। भारत में भी यह व्यवस्था लागू की जानी चाहिए।

यह समस्या केवल कोचिंग संस्थानों तक सीमित नहीं है। हॉस्टल, पीजी, छात्रावास और निजी आवासीय व्यवस्थाएं भी अक्सर सुरक्षा मानकों की अनदेखी करती हैं। अनेक स्थानों पर क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को रखा जाता है। संकरी सीढ़ियां,बंद खिड़कियां और खराब विद्युत व्यवस्था जोखिम को कई गुना बढ़ा देती हैं। इसलिए सुरक्षा का दायरा व्यापक रूप से देखा जाना चाहिए। प्रशासन की भूमिका भी इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुर्घटना के बाद जांच समिति गठित करना और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की घोषणा करना पर्याप्त नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि नियमित निरीक्षण और कठोर निगरानी की व्यवस्था विकसित की जाए। प्रत्येक शहर में कोचिंग संस्थानों और छात्रावासों का वार्षिक सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य होना चाहिए। जिन संस्थानों में गंभीर खामियां पाई जाएं, उन्हें सुधार तक संचालन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

इसके साथ ही स्थानीय निकायों और अग्निशमन विभाग को तकनीकी संसाधनों और मानवबल से मजबूत बनाना होगा। कई बार दुर्घटना के दौरान फायर ब्रिगेड समय पर नहीं पहुंच पाती। संकरी गलियां, ट्रैफिक और अपर्याप्त संसाधन राहत कार्यों को प्रभावित करते हैं। यदि हम वास्तव में ऐसी घटनाओं को रोकना चाहते हैं, तो आपातकालीन सेवाओं को अधिक सक्षम बनाना होगा। समाज और मीडिया की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। मीडिया को केवल सनसनीखेज तस्वीरें दिखाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उसे उन कारणों की गहराई से पड़ताल करनी चाहिए जो ऐसी घटनाओं को जन्म देते हैं। वहीं समाज को भी सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त करने से आगे बढ़कर सक्रिय भागीदारी करनी होगी। अभिभावक संगठनों, नागरिक समूहों और सामाजिक संस्थाओं को सुरक्षा मानकों की निगरानी और जागरूकता अभियान में भाग लेना चाहिए।

आज आवश्यकता एक सामूहिक आंदोलन की है। जिस प्रकार स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जन-जागरूकता अभियान चलाए गए,उसी प्रकार शैक्षणिक संस्थानों की सुरक्षा को लेकर भी व्यापक अभियान की जरूरत है। प्रत्येक अभिभावक,प्रत्येक छात्र और प्रत्येक नागरिक को यह समझना होगा कि सुरक्षा कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं, बल्कि मौलिक अधिकार है।

सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम अक्सर हादसों से सीखते नहीं हैं। दिल्ली, सूरत,राजकोट,कोटा और देश के कई अन्य हिस्सों में पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। हर बार जांच हुई, रिपोर्टें बनीं, सिफारिशें आईं और फिर धीरे-धीरे सब कुछ भुला दिया गया। यदि इस बार भी हम केवल शोक व्यक्त करके आगे बढ़ गए, तो यह उन मासूम बच्चों के प्रति अन्याय होगा जिनके सपने और जीवन इन दुर्घटनाओं की भेंट चढ़ जाते हैं।

अंततः यह समझना होगा कि बच्चों की सुरक्षा केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है और केवल अभिभावकों का दायित्व भी नहीं। यह एक साझा उत्तरदायित्व है जिसमें संस्थान, सरकार, समाज, मीडिया और परिवार सभी की भूमिका है। जब तक जवाबदेही की संस्कृति विकसित नहीं होगी,तब तक नियम केवल कागजों में रहेंगे और हादसे दोहराए जाते रहेंगे।

आज आवश्यकता है कि हर अभिभावक अपने बच्चे के संस्थान की सुरक्षा व्यवस्था की व्यक्तिगत रूप से जांच करे। संचालकों से सवाल पूछे, प्रमाण मांगे और संतोषजनक उत्तर न मिलने पर आवाज उठाए। बच्चों के जीवन से बड़ा कोई समझौता नहीं हो सकता।

लखनऊ का यह अग्निकांड केवल एक शहर की त्रासदी नहीं है। यह पूरे देश के लिए चेतावनी है। यदि हम अब भी नहीं जागे, तो अगली खबर किसी और शहर से आएगी,किसी और परिवार की दुनिया उजड़ जाएगी और हम फिर वही सवाल पूछेंगे—क्या हमारे बच्चों की सुरक्षा सिर्फ खबर बनकर रह जाएगी? समय आ गया है कि इस सवाल का जवाब शब्दों से नहीं, ठोस कार्रवाई से दिया जाए।

लोकतंत्र की जड़ों में मठा डालते जन-प्रतिनिधि

जनादेश के विश्वास पर कुठारा घात

संजीव ठाकुर
रायपुर,छत्तीसगढ़

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से देश के तमाम राजनीतिक दलों ने दल बदल के इतने अलग-अलग उदाहरण पेश किए हैं कि जनता का राजनीतिक पार्टियों और राजनेताओं से विश्वास और भरोसा धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। इतने खर्चीले चुनाव के बाद मिले जनादेश का अर्थ केवल सीटों की संख्या नहीं यह करोड़ों नागरिकों की सामूहिक इच्छा का सम्मान है। दल-बदल उसी जनादेश को छिन्न-भिन्न कर देता है। जनता ने जिस दल को विपक्ष में बैठने का दायित्व दिया था, उसके प्रतिनिधि यदि सत्ता में शामिल हो जाएँ,या जिन पर सरकार चलाने का भरोसा किया गया था वे दूसरी दिशा में चले जाएँ, तो मतदाता स्वयं को ठगा हुआ और असहाय महसूस करता है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी पूँजी विश्वास और भरोसा है, और दल-बदल उसी विश्वास और भरोसे पर बड़ा आघात करता है।

भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची के माध्यम से दल-बदल विरोधी कानून प्रभावशाली किया गया था ताकि निर्वाचित प्रतिनिधि निजी लाभ के लिए जनादेश का सौदा न कर सकें। किंतु समय के साथ राजनीतिक दलों ने ऐसे सुगम मार्ग खोज लिए जिनसे कानून की भावना बेबस पड़ गई। सामूहिक टूट, विलय और तकनीकी व्याख्याओं ने कानून की आत्मा को कई बार निष्प्रभावी बना दिया। परिणाम यह हुआ कि कानून मौजूद है, पर राजनीतिक नैतिकता लगातार कमजोर होती चली गई।

लोकतंत्र की रक्षा केवल न्यायालय, संविधान या चुनाव आयोग नहीं कर सकते। लोकतंत्र का वास्तविक प्रहरी वह जनप्रतिनिधि है जो अपने अंतःकरण के प्रति ईमानदार हो। यदि किसी सांसद या विधायक को सचमुच अपनी पार्टी की नीतियों से गंभीर वैचारिक असहमति है, तो लोकतांत्रिक मर्यादा यही कहती है कि वह पहले अपने पद से त्यागपत्र दे, फिर नए दल के टिकट पर जनता के बीच जाकर नया जनादेश प्राप्त करे। यदि जनता उसे पुनः चुनती है,तो वही उसकी वैध राजनीतिक स्वीकृति होगी। बिना इस्तीफा दिए दल बदलना नैतिक रूप से जनादेश का अपमान है।

आज राजनीति में सत्ता साधन नहीं, साध्य बनती जा रही है। मंत्री पद, राजनीतिक संरक्षण और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएँ कई बार जनहित से ऊपर दिखाई देती हैं। यही कारण है कि चुनाव के समय कटु विरोधी रहे नेता सत्ता की संभावनाएँ बनते ही एक-दूसरे के साथ खड़े दिखाई देते हैं। ऐसे दृश्य लोकतंत्र की गरिमा को कमज़ोर करते हैं और युवाओं के मन में राजनीति के प्रति अविश्वास पैदा करते हैं।

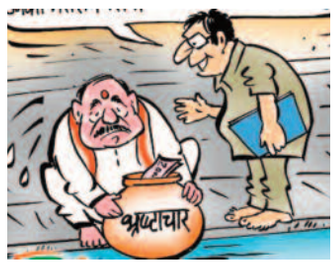

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसलिए यहाँ लोकतांत्रिक मर्यादाओं का स्तर भी सबसे ऊँचा होना चाहिए। लोकतंत्र केवल सरकार बनाने की

व्यवस्था नहीं है,बल्कि यह जनता के विश्वास,राजनीतिक नैतिकता और जनादेश की पवित्रता पर टिका हुआ एक जीवंत तंत्र है। मतदाता जब मतदान करता है, तो वह केवल किसी व्यक्ति को नहीं चुनता,बल्कि उसके विचार, उसकी पार्टी,उसकी नीतियों और उसके सार्वजनिक वचनों पर अपना विश्वास व्यक्त करता है। इसलिए निर्वाचित प्रतिनिधि का दल बदलना केवल राजनीतिक घटना नहीं,बल्कि लोकतांत्रिक आस्था पर गहरा आघात है। आज भारतीय राजनीति में दल-बदल की प्रवृत्ति जिस गति से बढ़ रही है,वह चिंता का विषय है। अनेक राज्यों में चुनाव के बाद सरकारों का स्वरूप जनादेश से कम और राजनीतिक जोड़-तोड़ से अधिक तय होता दिखाई देता है। कभी सत्ता पक्ष के विधायक विपक्ष में चले जाते हैं, तो कभी विपक्ष के सांसद सत्तारूढ़ दल का दामन थाम लेते हैं। यह प्रवृत्ति किसी एक दल तक सीमित नहीं है; लगभग सभी दल अवसर मिलने पर इसका लाभ उठाते रहे हैं। इसलिए यह किसी दल का नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्कृति के क्षरण का प्रश्न है। मूलत राजनीति का आधार विचारधारा होती है। कोई दल राष्ट्रवाद की बात करता है, कोई समाजवाद की,कोई सामाजिक न्याय की, तो कोई क्षेत्रीय अस्मिता की। किंतु जब वही नेता कुछ दिनों बाद विपरीत विचारधारा वाले दल में जाकर उसी के गुणगान करने लगते हैं, तब स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि क्या विचारधारा इतनी सस्ती है कि सत्ता के एक अवसर पर बदल जाए,यदि ऐसा है, तो चुनावी घोषणापत्र,सार्वजनिक भाषण और जनता से किए गए वादे केवल राजनीतिक अभिनय बनकर रह जाते हैं। जनादेश का अर्थ केवल सीटों की संख्या नहीं है;यह करोड़ों नागरिकों की सामूहिक इच्छा का सम्मान है। दल-बदल उसी जनादेश को विकृत कर देता है। जनता ने जिस दल को विपक्ष में बैठने का दायित्व दिया था,उसके प्रतिनिधि यदि सत्ता में शामिल हो जाएँ, या जिन पर सरकार चलाने का भरोसा किया गया था वे दूसरी दिशा में चले जाएँ, तो मतदाता स्वयं को ठगा हुआ महसूस करता है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी पूँजी विश्वास है, और दल-बदल उसी विश्वास का क्षरण करता है।

भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची के माध्यम से दल-बदल विरोधी कानून बनाया गया था ताकि निर्वाचित प्रतिनिधि निजी लाभ के लिए जनादेश का सौदा न कर सकें। किंतु समय के साथ राजनीतिक दलों ने ऐसे रास्ते खोज लिए जिनसे कानून की भावना कमजोर पड़ गई। सामूहिक टूट,विलय और तकनीकी व्याख्याओं ने कानून की आत्मा को कई बार निष्प्रभावी बना दिया। परिणाम यह हुआ कि कानून मौजूद है, पर राजनीतिक नैतिकता लगातार कमजोर होती चली गई। लोकतंत्र की रक्षा केवल न्यायालय, संविधान या चुनाव आयोग नहीं कर सकते। लोकतंत्र का वास्तविक प्रहरी वह जनप्रतिनिधि है जो अपने अंतःकरण के प्रति ईमानदार हो। यदि किसी सांसद या विधायक को सचमुच अपनी पार्टी की नीतियों से गंभीर वैचारिक असहमति है, तो लोकतांत्रिक मर्यादा यही कहती है कि वह पहले अपने पद से त्यागपत्र दे, फिर नए दल के टिकट पर जनता के बीच जाकर नया जनादेश प्राप्त करे। यदि जनता उसे पुनः चुनती है,तो वही उसकी वैध राजनीतिक स्वीकृति होगी। बिना इस्तीफा दिए दल बदलना नैतिक रूप से जनादेश का अपमान है। आवश्यकता इस बात की है कि दल-बदल कानून को और प्रभावी बनाया जाए। यदि कोई सांसद या विधायक स्वेच्छा से दल बदलता है,तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो तथा उसे अनिवार्य रूप से पुनः चुनाव लड़कर जनता का विश्वास प्राप्त करना पड़े। जनादेश किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं,बल्कि जनता की धरोहर है। साथ ही,राजनीतिक दलों को भी आत्ममंथन करना होगा। केवल दूसरे दलों के नेताओं का स्वागत करने की संस्कृति लोकतंत्र को स्वस्थ नहीं बनाएगी। यदि सभी दल सिद्धांतों को प्राथमिकता दें और अवसरवाद को अस्वीकार करें,तभी राजनीति का नैतिक स्तर ऊँचा उठ सकेगा।

स्मार्टफोन संयमित उपयोग की वैश्विक जरूरत

ललित गर्ग,पटपड़गंज,दिल्ली

विज्ञान और तकनीक ने मानव सभ्यता को अभूतपूर्व गति प्रदान की है। आज का युग डिजिटल युग है,जहां एक क्लिक पर पूरी दुनिया हमारी हथेली में सिमट आई है। स्मार्टफोन ने संचार, शिक्षा,व्यापार,बैंकिंग,स्वास्थ्य,शासन और सामाजिक संबंधों को नई दिशा दी है। लेकिन हर तकनीकी क्रांति अपने साथ कुछ गंभीर चुनौतियां भी लेकर आती है। स्मार्टफोन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह जितना बड़ा वरदान सिद्ध हुआ है, उतना ही बड़ा अभिशाप भी बनता जा रहा है। विशेष रूप से बच्चों और किशोरों पर इसके दुष्प्रभावों ने पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया है। आज विश्वभर में यह स्वीकार किया जा रहा है कि स्मार्टफोन केवल एक उपकरण नहीं,बल्कि एक ऐसी शक्ति है, जिसका विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है। दुर्भाग्यवश, विवेक और अनुशासन के अभाव में इसका नकारात्मक पक्ष अधिक मुखर हो रहा है। स्मार्टफोन की लत बच्चों और युवाओं में मानसिक तनाव, अवसाद, एकाकीपन,हिंसकप्रवृत्तियों, अश्लीलता, साइबर अपराध और सामाजिक विघटन का कारण बन रही है। यही कारण है कि आज केवल परंपरागत समाज और विकासशील देश ही नहीं,बल्कि विकसित देश भी इस चुनौती से निपटने के लिए कठोर कदम उठा रहे हैं। हाल ही में भारत के हरियाणा के नूंह जिले के सुखपुरी गांव की पहल ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। गांव की पहचान साइबर अपराध के केंद्र के रूप में बनने लगी थी। इससे आहत होकर ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से स्मार्टफोन त्यागने और बेसिक फोन अपनाने का निर्णय लिया। यह केवल मोबाइल तो ने की घटना नहीं,बल्कि समाज की उस पीड़ा की अभिव्यक्ति है,जो तकनीक के दुरुपयोग से उत्पन्न हुई है। गांव के युवाओं का विरोध भी स्वाभाविक है,क्योंकि आज शिक्षा, रोजगार,डिजिटल भुगतान और सरकारी सेवाएं स्मार्टफोन पर निर्भर हैं। इस घटना ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा किया है-क्या समाधान तकनीक का बहिष्कार है या उसके विवेकपूर्ण उपयोग का संस्कार? विश्व के अनेक देशों ने इस प्रश्न पर गंभीर चिंतन आरंभ कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन, नीदरलैंड, चीन और अमेरिका जैसे देशों में बच्चों और किशोरों के स्मार्टफोन उपयोग को नियंत्रित करने की दिशा में अनेक पहलें हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया ने किशोरों के सोशल मीडिया उपयोग पर आयु-सीमा तय करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। फ्रांस ने स्कूलों में स्मार्टफोन प्रतिबंध लागू किया है। ब्रिटेन में भी स्कूलों में मोबाइल उपयोग को सीमित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अमेरिका में सोशल मीडिया कंपनियों के विरुद्ध मुकदमे दायर हुए हैं और उन पर भारी जुर्माने लगाए गए हैं। इन पहलों का उद्देश्य तकनीक का विरोध नहीं,बल्कि बच्चों के मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है। वास्तव में स्मार्टफोन जहां वरदान है, वहीं अभिशाप भी है। इससे ज्ञान का भंडार भी उपलब्ध है और भ्रम का संसार भी। यह शिक्षा का माध्यम भी है और अश्लीलता तथा हिंसा का प्रवेश-द्वार भी। यह रोजगार के अवसर भी देता है और साइबर अपराध की राह भी खोलता है। आज अनेक युवा रातों-रात अमीर बनने की लालसा में साइबर ठगी, सेक्सटॉर्शन, ऑनलाइन जुआ और डिजिटल धोखाधे ी जैसे अपराधों में फंस रहे हैं। सोशल मीडिया पर फैल रही अश्लील सामग्री, फेक न्यूज, नफरत और ट्रोल संस्कृति ने सामाजिक मूल्यों को गहरी चोट पहुंचाई है। सबसे अधिक चिंता का विषय बच्चों और किशोरों का मानसिक स्वास्थ्य है।

हादसों का मंज़र व्यवस्था की लापरवाही

अजय कुमार,लखनऊ,उत्तरप्रदेश

आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले एक शाश्वत सत्य कहा था कि बुद्धिमान शासक वही है जो आने वाले संकट को पहले से भांप ले और उसके निराकरण का उपाय करे। लेकिन आज के लोकतंत्र में जब हम लखनऊ की उस तीन मंजिला इमारत को लाक्षागृह बनते देखते हैं,जहां 15 मासूम चिराग एक साथ बुझ गए,तो चाणक्य की वह सीख एक तंज की तरह चुभती है। यह महज एक हादसा नहीं है,बल्कि उस प्रशासनिक शीतनिद्रा का परिणाम है जो केवल लाशों के ढेर पर ही जागती है। लखनऊ के अलीगंज में जो हुआ,वह कोई इत्तेफाक नहीं था। यह उस जर्जर और भ्रष्ट व्यवस्था का निचोड़ है,जहां सुरक्षा मानकों को फाइलों के भीतर दफन कर दिया जाता है और भ्रष्टाचार को धरातल पर फलने-फूलने का मौका दिया जाता है।

सवाल यह नहीं है कि कोचिंग सेंटर में आग क्यों लगी, सवाल यह है कि कोचिंग सेंटर वहां क्यों चल रहा था? 2014 में जिस इमारत का नक्शा आवासीय उपयोग के लिए पास हुआ, वह कब और कैसे एक व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स में तब्दील हो गई? 2016 में जब लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उस अवैध निर्माण को ढहाने का आदेश दिया था, तो महज दो महीने बाद वह आदेश किस चमत्कारिक दबाव में रद्द कर दिया गया? इन 10 वर्षों के अंतराल में 30 इंजीनियर और जोनल अधिकारी उस क्षेत्र से गुजरे,क्या किसी की नजर उस इमारत की अवैध व्यावसायिक गतिविधि पर नहीं पड़ी? आंकड़े चीख-चीख कर कह रहे हैं कि यह लापरवाही का नहीं,बल्कि मिलीभगत का एक सुनियोजित तंत्र है। एलडीए के सूत्रों की मानें तो शहर में 30 हजार से अधिक आवासीय भूखंडों पर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स खड़े हैं और इनके पीछे इंजीनियरों की एक तय रेट लिस्ट काम करती है। एक चार मंजिला अवैध इमारत के निर्माण पर 20 से 25 लाख रुपये की वसूली का खेल चलता है। जब व्यवस्था ही पैसों की नींव पर टिकी हो, तो सुरक्षा की उम्मीद करना ही बेमानी है।

लखनऊ का यह हादसा दिल्ली के मालवीय नगर के होटल और बिहार के निजी अस्पताल की घटनाओं की कड़वी यादें ताजा कर देता है। हर बार घटना के बाद सिस्टम का वही पुराना स्क्रिप्टेड ड्रामा शुरू होता है। हादसे के अगले ही दिन प्रशासन अति-सक्रिय हो जाता है, सीलिंग की कार्रवाई होती है, अधिकारियों को सस्पेंड किया जाता है और कुछ दिनों के लिए एक खौफ का माहौल बनाया जाता है। लेकिन क्या यह समाधान है? कानपुर में 30 से अधिक बड़ी कोचिंग संस्थाओं को सील कर देना, प्रयागराज और वाराणसी में धड़ाधड़ कार्रवाई करना यह सब महज एक स्वांग है। अगर यही फुर्ती हादसे से पहले दिखाई गई होती, तो उन 15 घरों के बुझ चुके चिराग आज अपनी कक्षाओं में पढ़ रहे होते। ब्रिटिश दार्शनिक एडमंड बर्क ने सही कहा था कि समय पर सावधानी बरतना बाद में पछताने से कहीं बेहतर है। दुर्भाग्य यह है कि हमारे यहां प्रशासन सावधानी के बजाय हादसे के बाद दिखावटी कार्रवाई को अपनी जिम्मेदारी समझता है। इस पूरे प्रकरण की सबसे दर्दनाक कड़ी वह फायरमैन का वायरल वीडियो है, जिसने व्यवस्था की चूलें हिला दी हैं। एक पढ़ा-लिखा सिपाही जब अपनी जान जोखिम में डालकर यह आरोप लगाता है कि असली दोषी बड़े अधिकारी हैं, तो सिस्टम का चेहरा और भी घिनौना हो जाता है। जब तक नीचे के कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाया जाता रहेगा और मलाई खाने वाले अधिकारी सुरक्षित रहेंगे, तब तक जवाबदेही कभी तय नहीं हो पाएगी। मुख्यमंत्री ने मिशन मोड में फायर सेफ्टी ऑडिट के निर्देश दिए हैं, जो स्वागत योग्य है, लेकिन यह ऑडिट कागजों की खानापूर्ति बनकर न रह जाए, इसकी गारंटी कौन लेगा? क्या हर अस्पताल, नर्सिंग होम और कोचिंग सेंटर का वास्तविक ऑडिट होगा, या फिर वही पुरानी परंपरा चलेगी जहां एनओसी केवल टेबल के नीचे के लेन-देन से मिल जाती है?

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

-सम्पादक

संप्रेक्षण गृह से 11 अपचारी बालक फरार, सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त, जिम्मेदार मौन

और सवालों के घेरे में पूरा तंत्र

कुल 31 बालक थे मौजूद, 11 हुए फरार

- फरवरी में 15 बालक भागे थे, जून में फिर 11 फरार
- जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल संरक्षण अधिकारी मौजूद, फिर भी मीडिया के सामने आया हाउस फादर
- सभी फरार अपचारी बालक खिड़की के रास्ते से भागे
- पूरे परिसर में नहीं है सीसीटीवी कैमरा
- इमरजेंसी लाइट थी, फिर भी काम नहीं किया
- कलेक्टर, एसडीएम सहित उच्च अधिकारीयों ने किया निरीक्षण
- खराब खिड़की, कमजोर दीवार और लापरवाह स्टाफ पर उठे सवाल

वरिष्ठ अधिकारी मौजूद, बयान देने भेजा गया हाउस फादर

सीसीटीवी नहीं, सुरक्षा के दावे झूठे निकले!

खिड़की तोड़ने के औजार कहां से आए?

लाखों खर्च के बाद भी सुरक्षा व्यवस्था चरमराई

संप्रेक्षण गृह से 11 अपचारी बालक फरार...सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त,जिम्मेदार मौन और सवालों के घेरे में पूरा तंत्र...

फरवरी में 15 बालक भागे थे,जून में 11 फिर फरार,आखिर कब जागेगा बाल संरक्षण विभाग?

- जिले के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद...फिर भी मीडिया के सामने बयान देने भेज दिया गया हाउस फादर
- 31 अपचारी बालकों में से 11 खिड़की तोड़कर फरार...पूरे परिसर में सीसीटीवी व्यवस्था तक नहीं...

-संवाददाता-
अंबिकापुर,24 जून 2026 (घटती-घटना)।

अंबिकापुर के संप्रेक्षण गृह से 11 अपचारी बालकों के फरार होने की घटना ने एक बार फिर बाल संरक्षण व्यवस्था की गंभीर खामियों को उजागर कर दिया है,फरवरी में प्लेस ऑफ सेफ्टी से 15 बालकों के फरार होने की घटना के बाद भी यदि सुरक्षा व्यवस्था नहीं सुधरी और अब फिर 11 अपचारी बालक फरार हो गए,तो यह केवल एक घटना नहीं बल्कि पूरे तंत्र की विफलता का प्रमाण माना जा रहा है, जानकारी के अनुसार घटना के समय संप्रेक्षण गृह में कुल 31 अपचारी बालक मौजूद थे,जिनमें से 11 बालक खिड़की के रास्ते फरार हो गए। अब तक केवल एक बालक के वापस आने की जानकारी सामने आई है, जबकि 10 अन्य बालकों की तलाश जारी है।

वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे,फिर मीडिया से बात करने क्यों भेजा गया हाउस फादर?

घटना के बाद पत्रकारों से चर्चा करने और आधिकारिक जानकारी देने के लिए जिस व्यक्ति को सामने लाया गया, वह हाउस फादर था, हैरानी की बात यह है कि उस दौरान मौके पर जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल संरक्षण अधिकारी सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद बताए जा रहे थे,ऐसे में सवाल उठता है कि जब जिम्मेदार अधिकारी मौके पर मौजूद थे तो उन्होंने स्वयं सामने आकर मीडिया के सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया? क्या विभाग के पास घटना को लेकर स्पष्ट जवाब नहीं था? क्या जिम्मेदारी तय होने के डर से वरिष्ठ अधिकारी मीडिया से दूरी बनाते रहे? या फिर विभाग केवल निचले कर्मचारियों को आगे कर अपनी जवाबदेही से बचने का प्रयास कर रहा है? यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मामला सामान्य नहीं बल्कि बाल सुरक्षा से जुड़ी गंभीर चूक का है।

पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे तक नहीं,फिर सुरक्षा के दावे किस आधार पर?-

घटना के बाद सामने आई सबसे चौंकाने वाली जानकारी यह है कि संप्रेक्षण गृह के पूरे परिसर में पर्याप्त सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था तो है पर कुछ जगह, जहा होना चाहिए वह नहीं है, आज जब छोटे-छोटे कार्यालयों, दुकानों और निजी संस्थानों तक में सीसीटीवी निगरानी अनिवार्य मानी जाती है, तब कानून के संरक्षण में रखे गए अपचारी बालकों के संस्थान में निगरानी व्यवस्था का अभाव कई गंभीर प्रश्न खड़े करता है, यदि पूरे परिसर कैमरे नहीं हैं तो–गतिविधियों की निगरानी कैसे होती है? रात्रिकालीन सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है? किसी घटना की जांच किस आधार पर की जाएगी? फरार होने की पूरी प्रक्रिया का सत्यापन कैसे होगा? यह स्थिति सुरक्षा व्यवस्था की वास्तविक तस्वीर सामने रखती है।

सभी बालक खिड़की के रास्ते भागे...तो खिड़की ही सबसे कमजोर कड़ी थी?

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सभी 11 अपचारी बालक खिड़की के रास्ते फरार हुए, अब सवाल यह है कि खिड़की की सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी? क्या उसमें मजबूत ग्रिल लगी थी? क्या नियमित निरीक्षण होता था? खिड़की तोड़ने या खोलने के लिए आवश्यक साधन बालकों तक कैसे पहुंचे? एक साथ 11 बालकों का खिड़की के रास्ते निकल जाना यह संकेत देता है कि यह कोई अचानक हुई घटना नहीं बल्कि सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरी का लाभ उठाकर की गई सुनियोजित फरारी हो सकती है।

फरवरी की घटना से क्या सीखा गया था?

फरवरी में प्लेस ऑफ सेफ्टी से 15 बालकों के फरार होने के बाद विभाग ने क्या कदम उठाए थे? क्या सुरक्षा ऑडिट हुआ था? क्या अतिरिक्त स्टाफ की नियुक्ति की गई? क्या सुरक्षा उपकरणों को दुरुस्त किया गया? क्या जिम्मेदार कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई? यदि यह सब हुआ था तो फिर जून में वही कहानी दोबारा कैसे दोहराई गई? और यदि नहीं हुआ था, तो क्या यह मान लिया जाए कि विभाग ने पहली घटना को गंभीरता से लिया ही नहीं?

कलेक्टर,एसडीएम सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने किया निरीक्षण

घटना के बाद कलेक्टर, एसडीएम तथा अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने संप्रेक्षण गृह पहुंचकर निरीक्षण किया,निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था,परिसर की संरचना और घटना की परिस्थितियों की जानकारी ली गई, लेकिन जनता अब यह जानना चाहती है कि निरीक्षण के बाद क्या केवल रिपोर्ट बनेगी या वास्तव में जिम्मेदारी भी तय होगी? क्योंकि फरवरी की घटना के बाद भी निरीक्षण और समीक्षा की बातें हुई थीं, लेकिन परिणाम क्या निकला, यह आज दूसरी घटना के रूप में सामने है।

लाखों का बजट,लेकिन सुरक्षा भगवान भरोसे- बाल संरक्षण संस्थानों के संचालन,सुरक्षा,निगरानी और रखरखाव पर हर वर्ष लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं, लेकिन जब न पर्याप्त सीसीटीवी व्यवस्था हो,न मजबूत सुरक्षा तंत्र,न प्रभावी निगरानी और न जवाबदेही, तब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर यह धन खर्च कहां हो रहा है? कागजों में सुरक्षा और जमीनी हकीकत में लापरवाही का यह अंतर अब जांच का विषय बनना चाहिए।

जनता पूछ रही है...

- फरवरी में 15 और जून में 11 बालक फरार, आखिर जिम्मेदार कौन?
- पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं हैं?
- वरिष्ठ अधिकारी मौजूद होने के बावजूद मीडिया से बात करने हाउस फादर को क्यों भेजा गया?
- खिड़की के रास्ते फरारी कैसे संभव हुई?
- खिड़की तोड़ने के लिए साधन कहां से आए?
- सुरक्षा व्यवस्था की नियमित समीक्षा क्यों नहीं हुई?
- फरवरी की घटना में किस पर कार्रवाई हुई थी?
- क्या इस बार भी मामला जांच समिति तक सीमित रहेगा?

यह केवल फरारी नहीं, व्यवस्था पर अविश्वास का मामला है- *अंबिकापुर की यह घटना केवल 11 अपचारी बालकों के फरार होने की खबर नहीं है, यह उस व्यवस्था की विफलता का प्रतीक है, जो बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है, लेकिन बार-बार उन्हीं बच्चों को सुरक्षित रखने में असफल साबित हो रही है, जब कुछ ही महीनों में दो बड़े फरारी कांड सामने आ जाएं, वरिष्ठ अधिकारी जवाब देने से बचते दिखें,पूरे परिसर में सीसीटीवी जैसी मूलभूत व्यवस्था तक न हो और सुरक्षा की कमियां लगातार उजागर होती रहें, तब सवाल केवल फरार बालकों का नहीं रहता, बल्कि पूरे प्रशासनिक और बाल संरक्षण तंत्र की जवाबदेही का बन जाता है,अब देखना यह है कि इस बार भी जांच, निरीक्षण और बैठकों तक मामला सीमित रहता है या फिर वास्तव में जिम्मेदारी तय कर व्यवस्था में सुधार के ठोस कदम उठाए जाते हैं।*

सरगुजा महाराज स्व. मदनेश्वर शरण सिंहदेव की 25वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि, लोकसेवा के योगदान को किया याद

राजीव भवन में श्रद्धांजलि सभा के बाद प्रतिमा पर माल्यार्पण, महामाया मंदिर में आयोजित हुआ भंडारा

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,24 जून 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा महाराज एवं अविभाजित मध्यप्रदेश योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे स्व. मदनेश्वर शरण सिंहदेव की 25वीं पुण्यतिथि पर आज राजीव भवन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके लोकसेवा और समाजहित में किए गए कार्यों को याद किया।

श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद बस स्टैंड स्थित स्व. महाराज साहब एवं राजमाता स्व. देवेंद्र कुमारी सिंहदेव की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके पश्चात मां महामाया मंदिर में भंडारे का आयोजन कर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि राजपरिवार के प्रमुख उत्तराधिकारी होने के बावजूद स्व. मदनेश्वर शरण सिंहदेव ने जनसेवा का मार्ग चुना और भारतीय प्रशासनिक सेवा के माध्यम से समाज और प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वर्ष 1954 में द्वस् अधिकारी के रूप में चयनित होने के बाद उन्होंने प्रशासनिक सेवा में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं और कलेक्टर से लेकर राज्य के मुख्य सचिव जैसे सर्वोच्च प्रशासनिक पद तक पहुंचे। अपने कार्यकाल में उन्होंने भू-खातों के लिए ऋण पुस्तिका व्यवस्था,भूमिहीन परिवारों को भूमि आबंटन सहित कई जनहितकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मध्यप्रदेश को सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी बनाने में भी उनके योगदान को याद किया गया। तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में उन्होंने सोयाबीन खेती को बढ़ावा देने की योजनाओं पर विशेष कार्य किया था। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उनके जीवन,प्रशासनिक योगदान और समाजसेवा के कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई।

आपातकाल के 51 साल बाद भी सियासत गरम : भाजपा ने कांग्रेस पर साधा निशाना...कहा...'लोकतंत्र की हत्या का सबसे काला दौर था आपातकाल'

ओम प्रकाश सिन्हा बोले- सत्ता बचाने के लिए लगाया गया था आपातकाल,प्रेस और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हुआ था हमला

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,24 जून 2026 (घटती-घटना)।

भारतीय लोकतंत्र के इतिहास के सबसे विवादित दौर आपातकाल (1975-77) की 51वीं बरसी पर एक बार फिर सियासी बहस तेज हो गई है। भाजपा जिला सरगुजा ने संकल्प भवन स्थित जिला कार्यालय में प्रेसवार्ता आयोजित कर कांग्रेस पर तीखे राजनीतिक हमले किए। भाजपा नेताओं ने आपातकाल को लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हुए इसे कांग्रेस शासन की तानाशाही प्रवृत्ति का उदाहरण बताया। प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा संगठन जिला प्रभारी बलरामपुर एवं पूर्व जिलाध्यक्ष जशपुर ओम प्रकाश सिन्हा ने कहा कि 25 जून 1975 की आधी रात को लगाया गया आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय है। उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय संकट के कारण नहीं बल्कि अपनी सत्ता बचाने के लिए देश में आपातकाल लागू किया था। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा चुनाव निरस्त किए जाने के बाद तत्कालीन सरकार ने लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव बनाया। आपातकाल के दौरान प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगाई गई, विपक्षी नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेलों में बंद किया गया तथा नागरिकों के अधिकारों को सीमित कर दिया गया।

लोकतंत्र की आवाज दबाने का प्रयास था आपातकाल...

ओम प्रकाश सिन्हा ने कहा कि लोकतंत्र केवल चुनाव कराने से नहीं चलता,बल्कि इसमें स्वतंत्र मीडिया, मजबूत न्यायपालिका और जनता की असहमति का सम्मान जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि आपातकाल के दौरान इन सभी संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने भी उस समय की परिस्थितियों को लोकतंत्र के लिए गंभीर संकट बताया था। भाजपा नेता ने कहा कि आपातकाल की घटनाओं को याद करना इसलिए जरूरी है ताकि नई पीढ़ी समझ सके कि लोकतंत्र की रक्षा कितनी महत्वपूर्ण है।

कांग्रेस की कार्यशैली पर उठाए सवाल प्रेसवार्ता में भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आपातकाल केवल इतिहास की घटना नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति चेतावनी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की राजनीति में आज भी विरोध की आवाजों को दबाने और संस्थाओं पर प्रभाव डालने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। हालांकि कांग्रेस की ओर से समय-समय पर यह कहा जाता रहा है कि आपातकाल एक ऐतिहासिक राजनीतिक निर्णय था,जिसकी समीक्षा लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हो चुकी है।

विधायक प्रबोध मिंज बोले...लोकतंत्र सेनानियों का देश ऋणी

लुण्ड्रा विधायक प्रबोध मिंज ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र करोड़ों लोगों के संघर्ष और संविधान निर्माताओं की सोच का परिणाम है। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान नागरिक अधिकारों का हनन हुआ और लोकतंत्र की मूल भावना को चोट पहुंची। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतंत्र,संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आपातकाल के विरोध में संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा।

मशाल जुलूस और कार्यक्रमों की जानकारी

जिला महामंत्री विनोद हर्ष ने बताया कि आपातकाल की बरसी के अवसर पर 24 जून की शाम भाजपा सरगुजा द्वारा मशाल जुलूस निकाला गया। इसके अलावा आगामी दिनों में सम्मेलन एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे,जिनमें आपातकाल के दौरान हुए घटनाक्रम और लोकतंत्र की रक्षा के महत्व पर चर्चा की जाएगी। प्रेसवार्ता में लुण्ड्रा विधायक प्रबोध मिंज,महापौर श्रीमती मंजूषा भगत,जिला महामंत्री विनोद हर्ष,जिला संवाद प्रमुख रूपेश दुबे और जशपुर नगरपालिका अध्यक्ष अरविंद भगत सहित भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे।

CMYK

14 साल पुराने करोड़ों के फर्नीचर घोटाले की फाइलें फिर खुलीं

ACB की दबिश,कार्यालय से जब्त किए दस्तावेज,12 फर्म और कई अधिकारी जांच के घेरे में

राजीव गांधी शिक्षा मिशन में 2011-12 की खरीदी पर फिर उठे सवाल,हार्ड कॉपी से लेकर डिजिटल रिकॉर्ड तक खंगाले गए...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,24 जून 2026
(घटती-घटना)।

सरगुजा जिले के बहुचर्चित और करोड़ों रुपए के फर्नीचर घोटाले की जांच एक बार फिर तेज हो गई है। लगभग 14 वर्ष पुराने इस मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बुधवार को राजीव गांधी शिक्षा मिशन (वर्तमान समग्र शिक्षा) के जिला परियोजना कार्यालय में दबिश देकर महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी। एसीबी की इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग और मिशन कार्यालय में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। सूत्रों के अनुसार वर्ष 2011-12 में स्कूलों के लिए फर्नीचर खरीदी के नाम पर बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई थीं। जांच के दौरान विभागीय अधिकारियों और सप्लायर फर्मों की मिलीभगत से शासकीय राशि के दुरुपयोग के आरोप लगे थे। इसी मामले में पहले अपराध दर्ज किया गया था और अब जांच एजेंसी साक्ष्यों को और मजबूत करने में जुटी हुई है।

क्या है पूरा फर्नीचर घोटाला?

वर्ष 2011-12 में राजीव गांधी शिक्षा मिशन के माध्यम से जिले के विभिन्न स्कूलों में फर्नीचर उपलब्ध कराने के लिए करोड़ों रुपए की खरीदी की गई थी। आरोप है कि खरीदी प्रक्रिया में निर्धारित नियमों और वित्तीय प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। कई मामलों में बाजार मूल्य से अधिक दरों पर सामग्री खरीदे जाने, निविदा प्रक्रिया में अनियमितता बरतने तथा चयनित फर्मों को लाभ पहुंचाने के आरोप सामने आए थे। जांच में यह भी सामने आया था कि कुछ फर्मों को अनुचित तरीके से लाभ पहुंचाया गया, जबकि खरीदी संबंधी कई दस्तावेजों में गंभीर विसंगतियां पाई गई थीं। मामले के उजागर होने के बाद इसकी जांच शुरू हुई और कई अधिकारियों तथा सप्लायरों की भूमिका संदेह के घेरे में आ गई।

दस्तावेज नहीं मिलने पर कार्यालय पहुंची जांच टीम

जानकारी के मुताबिक एसीबी लंबे समय से मामले से जुड़े मूल दस्तावेजों और अभिलेखों की मांग कर रही थी,लेकिन आवश्यक रिकॉर्ड समय पर उपलब्ध नहीं कराए जा रहे थे। इसके बाद जांच एजेंसी की टीम सीधे जिला परियोजना कार्यालय पहुंची और वहां मौजूद फाइलों,क्रय प्रक्रिया से संबंधित दस्तावेजों,भुगतान रजिस्टर,बिल-वाउचर, निविदा रिकॉर्ड और अन्य अभिलेखों की गहन जांच शुरू की। टीम ने कार्यालय में रखे कंप्यूटर सिस्टम,डिजिटल डेटा,स्टोरेज डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी खंगाले। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए जाने की जानकारी सामने आई है। एसीबी अधिकारी अब इन दस्तावेजों का परीक्षण कर यह पता लगाने का प्रयास करेंगे कि खरीदी प्रक्रिया में किस स्तर पर नियमों का उल्लंघन किया गया।

डिजिटल साक्ष्यों पर विशेष फोकस...

इस बार की जांच में एसीबी केवल कागजी दस्तावेजों तक सीमित नहीं है। जांच एजेंसी डिजिटल रिकॉर्ड, कंप्यूटर डेटा,ई-मेल संचार,भुगतान से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की भी पड़ताल कर रही है। अधिकारियों का मानना है कि इतने पुराने मामले में डिजिटल रिकॉर्ड कई महत्वपूर्ण तथ्य उजागर कर सकते हैं।

12 फर्म और कई अधिकारी जांच के घेरे में...

जांच एजेंसियों के रिकॉर्ड के अनुसार इस मामले में विभागीय क्रय समिति से जुड़े तत्कालीन 6 से 7 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी। वहीं करीब 12 सप्लायर फर्मों के संचालकों के नाम भी जांच में सामने आए थे। एफआईआर में विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों और संबंधित फर्म संचालकों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत अपराध दर्ज किया गया था। इसके अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) एवं 13(2) के तहत भी प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।

कार्रवाई से बढ़ी अधिकारियों की चिंता

एसीबी की अचानक कार्रवाई के बाद मिशन कार्यालय के कर्मचारियों और पूर्व में पदस्थ रहे अधिकारियों के बीच चर्चा का माहौल है। जांच एजेंसी द्वारा जब्त किए गए दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद कई नए तथ्य सामने आने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों का कहना है कि यदि दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों में आरोपों की पुष्टि होती है तो मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई तेज हो सकती है। वहीं जांच के दायरे में आने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और फर्म संचालकों की जवाबदेही भी तय की जा सकती है।

एसीबी के सामने है कई चुनौती?

एसीबी अब जब्त दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड का परीक्षण करेगी। इसके बाद संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ, दस्तावेजों का मिलान और वित्तीय लेन-देन की समीक्षा की जाएगी। जांच एजेंसी की अगली रिपोर्ट इस बहुचर्चित घोटाले में आगे की कार्रवाई की दिशा तय होगा। करीब डेढ़ दशक पुराने इस मामले में एसीबी की ताजा कार्रवाई ने एक बार फिर उन सवालों को जीवित कर दिया है कि आखिर शिक्षा व्यवस्था के नाम पर खर्च किए गए करोड़ों रुपए का उपयोग नियमों के अनुरूप हुआ था या नहीं। अब सबकी नजर जांच के अगले चरण और संभावित कार्रवाई पर टिकी हुई है।

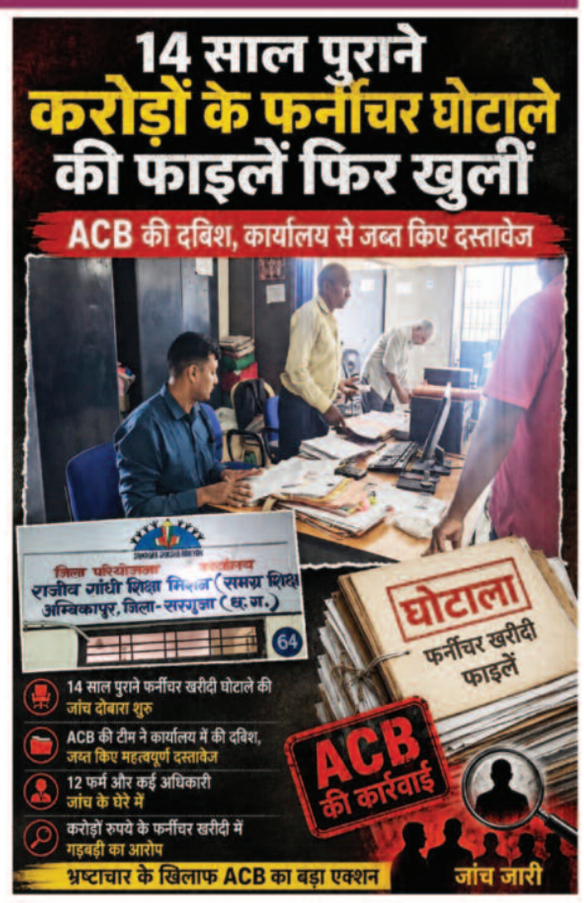

नगर सैनिक से मारपीट कर रेत से भरा वाहन छुड़ाने वाला मुख्य आरोपी लड्डन खान गिरफ्तार,2 अपचारी बालक भी पकड़े गए...

रेत तस्करों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई,साइबर सेल और गांधीनगर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,24 जून 2026
(घटती-घटना)।

रेत से भरे वाहन को पकड़कर ले जा रहे नगर सैनिक के साथ मारपीट कर वाहन छुड़ाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी लड्डन खान सहित 2 विधि से संघर्षरत बालकों को गिरफ्तार किया है। आरोपी लड्डन खान के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। यह कार्रवाई डीआईजी एवं सरगुजा एसएसपी राजेश अग्रवाल के दिशा-निर्देशन में थाना गांधीनगर पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने की।

जानकारी के अनुसार केंद्रीय उड़नदस्ता टीम (खनिज शाखा) रायपुर के नगर सैनिक तारकेश्वर वर्मा 22 जून को जांच कार्रवाई के दौरान सरगुजा पहुंचे थे। अधिकारियों के निर्देश पर उन्होंने रेत से भरे वाहन को अभिरक्षा में लेकर अंबिकापुर कलेक्ट्रेट परिसर ले जाना शुरू किया था। इसी दौरान वाहन चालक सोनू टोप्पो ने वाहन मालिक लड्डन खान का नाम बताते हुए नगर सैनिक को धमकी दी। गांधी चौक सिग्नल के पास वाहन मालिक लड्डन खान भी मौके पर पहुंच गया। आरोप है कि सभी आरोपियों ने नगर सैनिक के साथ गाली-गलौज और मारपीट की, उसकी वर्दी फाड़ने का प्रयास किया और उसे पकड़कर रखा, जिसके बाद वाहन चालक रेत से भरे वाहन को लेकर फरार हो गया। मामले में नगर सैनिक की रिपोर्ट पर थाना गांधीनगर में अपराध क्रमांक 386/26 के तहत बीएनएस की धाराओं 191(2), 221, 121(1), 132, 296, 351(3) में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए पहले ही आरोपी सोनू टोप्पो (19 वर्ष) और धनसिंह टोप्पो (35 वर्ष), दोनों निवासी सिलफिली पहाड़गांव थाना जयनगर जिला सूरजपुर को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी लड्डन खान (43 वर्ष), निवासी साईं मंदिर रोड वार्ड क्रमांक-1 भगवानपुर थाना गांधीनगर सहित दो विधि से संघर्षरत बालकों को पकड़ा। पूछताछ में आरोपियों ने घटना में शामिल होना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि अवैध गतिविधियों और रेत तस्करी में संलिप्त लोगों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी, उप निरीक्षक दिलीप दुबे, साइबर सेल प्रभारी सहायक उप निरीक्षक अजीत मिश्रा सहित पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

नशामुक्त भारत सप्ताह के तहत विशेष विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम, विद्यार्थियों ने ली नशामुक्ति की शपथ

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,24 जून 2026 (घटती-घटना)।

नशामुक्त भारत अभियान योजना के अंतर्गत आयोजित नशामुक्त भारत सप्ताह के तहत आज समाज कल्याण विभाग द्वारा होली क्रॉस आशा निकुंज श्रवण बाधित विशेष विद्यालय,अंबिकापुर में नशामुक्ति जनजागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों एवं विद्यालय स्टॉफ को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए नशामुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने नशामुक्त भारत अभियान की रूपरेखा,उद्देश्य तथा समाज में इसकी आवश्यकता पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर उपस्थित छात्र-छात्राओं को नशामुक्त भारत अभियान के तहत नशामुक्ति की शपथ दिलाई गई तथा स्वस्थ,सुरक्षित और जागरूक समाज के निर्माण में अपनी सहभागिता निभाने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षकगण, स्टॉफ तथा समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी उपस्थित रहे। अभियान के माध्यम से युवाओं और विद्यार्थियों में नशे के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा नशामुक्त समाज के निर्माण का संदेश दिया गया।

शराब पीकर वाहन चलाना पड़ा भारी,ड्रंक एंड ड्राइव के 2 मामलों में 20 हजार का जुर्माना

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,24 जून 2026 (घटती-घटना)।

सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात नियमों का पालन कराने पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में ड्रंक एंड ड्राइव के दो मामलों में वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए न्यायालय ने दोनों चालकों को कुल 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। डीआईजी एवं सरगुजा एसएसपी राजेश अग्रवाल के दिशा-निर्देशन में यातायात शाखा और थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा यह कार्रवाई की गई। पहले मामले में यातायात शाखा पुलिस टीम द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल क्रमांक CG-16-CQ-8675 के चालक को रोककर जांच की गई। चालक ने अपना नाम जीवन (20 वर्ष), निवासी खालपारा थाना दरिमा जिला सरगुजा बताया। जांच में चालक शराब के नशे में पाया गया। ब्रेथ एनालाइजर से जांच में भी शराब सेवन की पुष्टि हुई। वहीं दूसरे मामले में थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा देवरी रोड पर वाहन चेकिंग के दौरान हीरो ग्लैमर मोटरसाइकिल क्रमांक CG-16-CU-0169 के चालक प्रताप सिंह (22 वर्ष),निवासी बरगीडीह थाना लुंड्रा को रोका गया।

अवैध खाद भंडारण पर प्रशासन का बड़ा कार्रवाई, बतौली में 379 बोरी उर्वरक जब्त

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,24 जून 2026
(घटती-घटना)।

कलेक्टर श्री अजीत वसंत के निर्देशन एवं उप संचालक कृषि श्री पीतांबर सिंह दीवान के मार्गदर्शन में जिले में अवैध उर्वरक भंडारण एवं कालाबाजारी के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कृषि एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा विकासखंड बतौली के ग्राम पोकसरी एवं मंगरी में छापामार कार्रवाई कर बिना वैध दस्तावेजों के भंडारित बड़ी मात्रा में रासायनिक उर्वरक जब्त किया गया। प्राप्त सूचना के आधार पर संयुक्त टीम ने ग्राम पोकसरी निवासी श्री रामनरेश यादव के घर स्थित गोदाम का निरीक्षण किया। जांच के दौरान गोदाम में बिना किसी वैध दस्तावेज के भंडारित 206 बोरी यूरिया, 92 बोरी एनपीके तथा 55 बोरी डीएपी खाद बरामद की गई। इसके अतिरिक्त टीम ने मंगारी स्थित 'मां लक्ष्मी किराना स्टोर' में भी दबिश दी, जहां से 21 बोरी यूरिया एवं 5 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट (एसएसपी) बिना वैध दस्तावेज के भंडारित पाए गए। संयुक्त टीम द्वारा कुल 379 बोरी उर्वरक जब्त कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई तक संबंधित व्यक्ति की सुपुर्दगी में रखा गया है। इस कार्रवाई में कृषि विभाग की ओर से अनुविभागीय कृषि अधिकारी श्रीमती अनीता एक्का, सहायक संचालक कृषि श्री अभिषेक झा, उर्वरक निरीक्षक श्री पवन साय भगत, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री रविश गुप्ता एवं कृषि विकास अधिकारी श्री गब्बर सिंह नागवंशी तथा राजस्व विभाग की ओर से राजस्व निरीक्षक श्री धर्मेंद्र सिंह एवं पटवारी श्री अनुज सिन्हा शामिल रहे। जिले में आगामी दिनों में भी औचक निरीक्षण एवं सख्त वैधानिक कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

29 एवं 30 जून को होगा दो दिवसीय रामगढ़ महोत्सव

रामगढ़ प्राचीनतम ऐतिहासिक स्थल में भव्य महोत्सव का होगा आयोजन : मंत्री राजेश अग्रवाल

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,24 जून 2026 (घटती-घटना)।

आषाढ़ माह के प्रथम दिवस पर 29 एवं 30 जून को विकासखंड उदयपुर स्थित रामवनगमन पर्यटन स्थल रामगढ़ में दो दिवसीय रामगढ़ महोत्सव-2026 का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव की पूर्व तैयारियों एवं सफल आयोजन को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्री अजीत वसंत,वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री राजेश अग्रवाल,डीएफओ श्री अभिषेक जोगावत,जिला पंचायत सीईओ श्री विनय कुमार अग्रवाल,अपर कलेक्टर श्री रामसिंह ठाकुर,एसडीएम श्री बनसिंह नेताम,श्री रामराज सिंह, स्थानीय जनप्रतिनिधि,समिति के सदस्य,सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में रामगढ़ महोत्सव के सफल आयोजन हेतु एजेंडावार चर्चा करते हुए विभिन्न विषयों पर सुझाव दिए गए। महोत्सव के सुचारू संचालन के लिए पार्किंग व्यवस्था, रामजानकी मंदिर परिसर में सीता बेंगरा गुफा से रामजानकी मंदिर तक सड़क के दोनों किनारों पर प्रकाश एवं विद्युत व्यवस्था,कार्यक्रमों का शेड्यूल,सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, कार्यक्रम स्थल पर स्टॉल सजावट,राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी, कवि सम्मेलन,विद्यालयीन सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित अन्य व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

गणपति धाम के प्रवेश द्वार पर विराजीं भगवान गणेश की भव्य प्रतिमाएं,श्रद्धालुओं ने की पूजा-अर्चना

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,24 जून 2026
(घटती-घटना)।

हाथी पखना स्थित प्रसिद्ध गणपति धाम के मुख्य प्रवेश द्वार के अग्र भाग में दोनों ओर भगवान गणेश की भव्य प्रतिमाओं की स्थापना की गई। धार्मिक आस्था और भव्यता से जुड़े इस अवसर पर बाल गंगाधर तिलक गणपति स्थापना ट्रस्ट के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु गणपति धाम पहुंचे।

विधि-विधान के साथ भगवान गणेश की पूजा-अर्चना, आरती एवं मंत्रोच्चार के बीच प्रतिमाओं की स्थापना की गई। श्रद्धालुओं ने गणपति बप्पा के जयकारों के साथ क्षेत्र की सुख-समृद्धि और मंगलकामना की। ट्रस्ट के संरक्षक भारत सिंह सिसोदिया ने कहा कि गणपति धाम केवल पूजा-अर्चना का स्थल नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और सामाजिक एकता का केंद्र है। प्रवेश द्वार पर भगवान गणेश की प्रतिमाओं की स्थापना से धाम की धार्मिक गरिमा और आध्यात्मिक वातावरण को नई ऊर्जा मिलेगी। ट्रस्ट अध्यक्ष शैलेष सिंह शैलू ने कहा कि भगवान गणेश विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता के रूप में पूजे जाते हैं। प्रतिमाओं की स्थापना श्रद्धालुओं के लिए

आध्यात्मिक प्रेरणा और सकारात्मक ऊर्जा का माध्यम बनेगी। उन्होंने आयोजन में सहयोग देने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं समिति सदस्यों का आभार जताया। कार्यक्रम के अंत में भगवान गणेश की आरती कर प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान पूरा धाम परिसर भक्तिमय वातावरण से गूंज उठा। इस अवसर पर गणपति स्थापना ट्रस्ट के अध्यक्ष शैलेष सिंह शैलू, विनोद हर्ष, राजीव अग्रवाल,जितेंद्र सोनी,जन्मेजय मिश्रा, निलेश सिंह,मधुसूदन शुक्ला,रूपेश दुबे,जन्मेजय पांडेय,संजीव वर्मा,अजय सोनी,रामप्रवेश पांडेय,सरिता जायसवाल,अनीश सिंह, रवि विश्वकर्मा,आयुष दुबे,ईशु केशरवानी,सक्षम कश्यप,राजन सोनी,कान्हा अग्रवाल,राजा साहू, मोहित शर्मा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।

FORMAT OF TENDER NOTICE FOR PUBLICATION ON NEWS PAPERS

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH,
WATER RESOURCES DEPARTMENT
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER,
WATER RESOURCES DIVISION NO.1 AMBIKAPUR

e-Procurement Tender Notice

Main Portal: http://egeprocurement.gov.in
WRD Portal: http://wrd.cgeprocurement.gov.in

[FIRST-CALL]
Corrigendum-2

No. 02 /SAC/2026-27 Date 18-06-2026

IN N.I.T. No. 01/SAC /2026-27 Dated 02-06-2026 System Tender No. 192066 (1" Call), Whose "G" No. 262701221 Date. 05-06-2026 following amendments are made-

Previous published					Amendment			
Item No.	Qty.	Rate	Unit	Amount	Qty.	Rate	Unit	Amount
55	58.16	6153.39	Sqm	357881.16	62.10	6153.39	Sqm	382126
56	6.45	4576.02	Sqm	29515.33	6.75	4576.02	Sqm	30888
366	50	584.47	Each	29223.50	50	58.45	Each	2923

Executive Engineer
Water Resources Division No.1
Ambikapur
For-Chief Engineer
Hasdeo Ganga Basin, W.R. Deptt.
Ambikapur (C.G.)

G.N.-262701637/6

कार्यालय अधीक्षण अभियंता
लोक निर्माण विभाग सेतु मण्डल अम्बिकापुर (छ0ग0)
बाबूपारा जेल रोड़ अम्बिकापुर फोन 07774-224498 फैक्स 224113

ई-प्रोक्यूरमेंट निविदा सूचना
Portal:https://eproc.cgstate.gov.in

निम्नलिखित कार्य हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है :-
निविदा डाउनलोड करने की अंतिम तिथि - दिनांक 30.06.2026
निविदा आमंत्रण - द्वितीय आमंत्रण

स. क्र.	निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक व दिनांक	सिस्टम निविदा क.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (लाख में
1	2	3	4	5
1	04/ 16.06.2026	193543	लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग अंतर्गत उपसंभाग अम्बिकापुर, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़ एवं रामानुजगंज के अंतर्गत विभिन्न नदी नालों में बोरिंग कार्य का निविदा आमंत्रण बावत् ।	रू. 39.71 लाख
2	05/ 16.06.2026	193543	लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग अंतर्गत उपसंभाग जशपुर के अंतर्गत विभिन्न नदी नालों में बोरिंग कार्य का निविदा आमंत्रण बावत।	रू. 28.82 लाख

अधीक्षण अभियंता
लोक निर्माण विभाग सेतु मण्डल
अम्बिकापुर,जिला सरगुजा (छ0ग0)

जी.नं.- 262701622/4

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील भैयाथान जिला-सूरजपुर,छ0ग0

रा0प्र0क्र0 ब/121 वर्ष
ग्राम - प0ह0ग0

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक कृष्णा पिता विश्वनाथ जाति गोड़ निवासी ग्राम कुसमूसी प0ह0ग0 11 रा0नि0म0 भैयाथाना तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर छ0ग0 द्वारा पेश किया गया है कि आवेदक के पुत्री सुनीता का जन्म दिनाँक 12/07/2007 को ग्राम .... में हुई है अज्ञानतावश जन्म / मृत्यु पंजियन नही करा पाया है आवेदक अपने पुत्री सुनीता का जन्म/मृत्यु पंजीयन हेतु ग्राम प्रचायत कुसमूसी को आदेशित करने आवेदन पेश किया है जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधिन है।

अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 26/6/2026 तक अपना आपत्ति इस न्यायालय में पेश कर सकते है नियत तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार किया जावेगा ।

आज दिनाँक 18/06/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया ।

सील
कार्यपालिक दण्डाधिकारी
भैयाथान,जिला-सूरजपुर

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार -2 अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,(छ0ग0)

रा0प्र0क0 /ब-121/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक संजय कुजूर आ0 प्रेमू राम निवासी ग्राम अजिरमा तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ0ग0) मोबाईल नंबर 62660-95969 के द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि आवेदक के पिता प्रेमू राम आ0 बाहमन राम कि नियुक्ति C-A-F- में 27/11/1991 में आरक्षक के पद पर हुई थी, जो कि वर्ष 2026 में कंपनी कमांडर के पद पर कार्यरत थे, जिनका मृत्यु दिनांक 02/03/2026 को C-A-F- विभाग में कार्यरत रहते हुआ है। आवेदक के द्वारा अपने पिता के स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति हेतु वंशावली एवं आश्रित प्रमाण पत्र प्रदाय किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। जो अनुविभागीय अधिकारी (रा0) अम्बिकापुर के माध्यम से इस न्यायालय को जांच व प्रतिवेदन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

उक्त संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 17/07/2026 को न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।
आज दिनांक 24/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील
अतिरिक्त तहसीलदार,
अम्बिकापुर-2

-रवि सिंह-

कोरिया, 24 जून 2026 (घटती-घटना)।

किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने तथा पशुधन विकास को गति देने के उद्देश्य से संचालित की जा रही प्रायवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता योजना एवं वत्सो पालन योजना अब सवालों के घेरे में आ गई हैं। पशुपालन विभाग कोरिया में इन योजनाओं के संचालन को लेकर गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं,क्षेत्र में चर्चा है कि योजनाओं के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च तो दर्शाए गए,लेकिन धरातल पर अपेक्षित परिणाम दिखाई नहीं दे रहे हैं,ऐसे में विभागीय रिकॉर्ड और जमीनी हकीकत के बीच अंतर को लेकर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं।

सूत्रों के अनुसार जिले के विभिन्न विकासखंडों में कार्यरत निजी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं द्वारा हर माह बड़ी संख्या में पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान,गर्भधारण और वत्स (बछड़ा-बछिया) जन्म के आंकड़े विभाग को भेजे जाते रहे हैं, इन्हीं आंकड़ों के आधार पर योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाती है और शासन से प्राप्त राशि का भुगतान भी किया जाता है,लेकिन आरोप है कि इन आंकड़ों का कभी गंभीरता से भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया।

आंकड़ों और वास्तविकता में अंतर की चर्चा...

जानकारों और स्थानीय स्तर पर जुड़े लोगों का कहना है कि कई क्षेत्रों में विभाग को भेजे गए आंकड़े वास्तविक स्थिति से मेल नहीं खाते,आरोप है कि जिन गांवों और क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कृत्रिम गर्भाधान और पशु जन्म का दावा किया गया है,वहां उतनी संख्या में पशुधन ही उपलब्ध नहीं है, यदि इन दावों की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं, क्षेत्र में यह चर्चा भी है कि कई मामलों में कागजों में उपलब्धियां दिखाकर योजनाओं को सफल बताया गया, जबकि वास्तविक लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ अपेक्षित स्तर पर नहीं पहुंच सका,यदि यह आरोप सही साबित होते हैं तो यह केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला भी बन सकता है।

जांच की मांग हुई तेज...

अब पूरे मामले की उच्चस्तरीय और स्वतंत्र जांच की मांग उठने लगी है,लोगों का कहना है कि यह केवल वित्तीय अनियमितता का मामला नहीं है,बल्कि किसानों और पशुपालकों के अधिकारों से जुड़ा विषय है,यदि योजनाओं का लाभ वास्तविक हितग्राहियों तक नहीं पहुंचा और सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है,तो इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए,अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कागजों में दिखाई गई उपलब्धियां वास्तविक हैं या फिर करोड़ों रुपये की सरकारी राशि फर्जी आंकड़ों की भेंट चढ़ गई? इस सवाल का जवाब केवल निष्पक्ष और पारदर्शी जांच ही दे सकती है।

क्या बिना सत्यापन के स्वीकार किए गए आंकड़े?

सबसे गंभीर आरोप यह है कि प्रायवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों को विभागीय अधिकारियों ने बिना पर्याप्त जांच और सत्यापन के स्वीकार कर लिया। इसके बाद उन्हीं आंकड़ों के आधार पर योजनाओं की सफलता का दावा किया गया और भुगतान की प्रक्रिया पूरी की गई, आरोप लगाने वाले लोगों का कहना है कि यदि विभाग के पास वास्तविक लाभार्थियों की सूची, पशुओं का विवरण और जन्मे वत्सों का रिकॉर्ड मौजूद है तो उसे सार्वजनिक जांच के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए, इससे योजनाओं की पारदर्शिता भी बढ़ेगी और उठ रहे संदेह भी दूर होंगे।

एमसीबी जिले में भी उठ रहे सवाल...

सूत्रों का दावा है कि केवल कोरिया जिले में ही नहीं बल्कि मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले में भी इसी प्रकार की अनियमितताओं की चर्चा है, बताया जा रहा है कि कई मामलों में फर्जी या संदिग्ध आंकड़ों के आधार पर योजनाओं का क्रियान्वयन दर्शाया गया और शासन से प्राप्त राशि खर्च दिखाकर फाइलों का निपटारा कर दिया गया, हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन लगातार उठ रहे सवालों ने विभाग की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है।

गांव-गांव सत्यापन की मांग...

स्थानीय पशुपालकों, जनप्रतिनिधियों और जागरूक नागरिकों का कहना है कि पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने का सबसे प्रभावी तरीका भौतिक सत्यापन है, उनका सुझाव है कि विभाग की मासिक रिपोर्ट के आधार पर गांव-गांव जाकर लाभार्थियों, पशुओं और जन्मे वत्सों का सत्यापन कराया जाए, यदि रिकॉर्ड सही हैं तो विभाग की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, और यदि गड़बड़ी है तो दोषियों पर कार्रवाई का रास्ता खुलेगा।

जिल्दा खाद घोटाले में बड़े नामों पर कार्रवाई कब?

246.75 मीट्रिक टन खाद गबन मामले में एक गिरफ्तारी,बाकी नामों पर चुप्पी क्यों?

पोंडी बचरा चौकी के सामने अनिश्चितकालीन आंदोलन,किसानों ने उठाए कई बड़े सवाल...

-राजेंद्र शर्मा-

खड़गवां/पोंडी बचरा,24 जून 2026 (घटती-घटना)।

किसानों के लिए आवंटित 246.75 मीट्रिक टन उर्वरक खाद के कथित गबन और अवैध बिक्री से जुड़े जिल्दा खाद घोटाले को लेकर क्षेत्र में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है,मामले में जिल्दा सहकारी समिति के प्रबंधक अकिलचंद की गिरफ्तारी और जेल भेजे जाने के बाद अब आंदोलनकारियों और किसानों के बीच यह सवाल तेजी से उठ रहा है कि यदि घोटाले में केवल एक व्यक्ति जिम्मेदार था तो इतना बड़ा खेल कैसे हो गया,और यदि अन्य लोग भी इसमें शामिल थे तो उन पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्षेत्र में चर्चा है कि किसानों के लिए आवंटित खाद कथित रूप से व्यापारियों तक पहुंच गई और उसे ऊंचे दामों पर बेचने की तैयारी की गई,जबकि दूसरी ओर किसान खाद के लिए परेशान होते रहे, आरोप है कि जिस समय किसानों को खेती के लिए उर्वरक की सबसे अधिक आवश्यकता थी, उसी समय उनके हिस्से का खाद कथित रूप से गायब हो गया।

एक गिरफ्तारी के बाद भी बाकी नामों पर सवाल...

मामले में अब तक हुई कार्रवाई के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या इतना बड़ा खाद घोटाला केवल एक व्यक्ति के बूते संभव था? आंदोलनकारियों का कहना है कि जांच के दौरान कई नामों की चर्चा सामने आई, लेकिन उन पर कोई ठोस कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है, लोगों का कहना है कि यदि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी है तो पूरे नेटवर्क का खुलासा होना चाहिए,आखिर खाद का परिवहन किसने किया,उसे कहां रखा गया, किन लोगों ने खरीद-फरोख्त में भूमिका निभाई और किसके संरक्षण में पूरा कथित खेल संचालित हुआ? इन सभी सवालों के जवाब अभी भी जनता जानना चाहती है।

क्या राजनीतिक संरक्षण बन रहा ढाल?

जनआंदोलन से जुड़े लोगों का आरोप है कि मामले में कुछ प्रभावशाली लोगों के नाम चर्चा में होने के बावजूद जांच अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ रही है, क्षेत्र में यह चर्चा भी है कि कुछ लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है,जिसके कारण कार्रवाई सीमित दायरे में सिमटती दिखाई दे रही है, हालांकि इन आरोपों की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आंदोलनकारी खुलकर सवाल उठा रहे हैं कि यदि कानून सबके लिए समान है तो फिर सभी संदिग्ध और कथित जिम्मेदार लोगों तक जांच क्यों नहीं पहुंच रही? उनका कहना है कि जांच का उद्देश्य केवल एक आरोपी को जेल भेजना नहीं होना चाहिए,बल्कि पूरे मामले की तह तक पहुंचना और हर जिम्मेदार व्यक्ति की भूमिका स्पष्ट करना होना चाहिए।

पोंडी बचरा में अनिश्चितकालीन आंदोलन

खाद घोटाले को लेकर पोंडी बचरा पुलिस चौकी के सामने अनिश्चितकालीन जनआंदोलन जारी है। आंदोलनकारी किसानों के अधिकारों और खाद घोटाले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, उनका कहना है कि जब तक पूरे मामले का खुलासा नहीं होता और सभी दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन में शामिल लोगों का कहना है कि यह केवल खाद का मामला नहीं बल्कि किसानों के भरोसे और उनके अधिकारों का प्रश्न है, यदि किसानों के हिस्से का खाद बीच रास्ते में गायब हो जाए और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई न हो तो इससे पूरे सहकारी तंत्र की विश्वसनीयता प्रभावित होती है।

जनता से साथ आने की अपील...

आंदोलनकारियों ने क्षेत्र की जनता,किसानों और सामाजिक संगठनों से इस लड़ाई में साथ आने की अपील की है, उनका कहना है कि भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है।

कई सवालों के जवाब अभी बाकी...

मामले को लेकर अब भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब प्रशासन और जांच एजेंसियों से अपेक्षित है किसानों के हिस्से का 246.75 मीट्रिक टन खाद आखिर किन लोगों तक पहुंचा? क्या इस कथित गबन में केवल एक व्यक्ति की भूमिका थी? अन्य कथित सह-आरोपियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या राजनीतिक दबाव या संरक्षण के कारण जांच प्रभावित हो रही है? किसानों को खाद संकट झेलना पड़ा, इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? क्या पूरे मामले की उच्चस्तरीय और स्वतंत्र जांच कराई जाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में जांच की दिशा और प्रशासन की मंशा दोनों को स्पष्ट करेंगे, फिलहाल क्षेत्र की जनता और किसान एक ही मांग कर रहे हैं–खाद घोटाले की निष्पक्ष जांच हो और दोषी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उस पर कानून के अनुसार कार्रवाई हो।

मनेन्द्रगढ़ को बड़ी सौगात

नर्सिंग महाविद्यालय भवन निर्माण के लिए 8.68 करोड़ से अधिक की स्वीकृति

868.35 लाख से बनेगा शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय भवन

स्थानीय युवाओं को घर के पास मिलेगी उच्च गुणवत्तापूर्ण नर्सिंग शिक्षा

दूरस्थ क्षेत्रों तक चिकित्सा शिक्षा पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता : स्वास्थ्य मंत्री

-संवाददाता-

रायपुर/मनेन्द्रगढ़,24 जून 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मनेन्द्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी (एमसीबी) जिले को एक बड़ी सौगात देते हुए शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, मनेन्द्रगढ़ के भवन निर्माण के लिए 868.35 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की है,इस स्वीकृति के बाद जिले में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित होने की उम्मीद जताई जा रही है,स्वीकृत राशि से नर्सिंग महाविद्यालय के लिए आवश्यक भवन और बुनियादी अधोसंरचना का विकास किया जाएगा, इसमें नर्सिंग शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों के संचालन तथा लोक स्वास्थ्य एकीकरण से जुड़े आवश्यक प्रावधान भी शामिल हैं।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस महत्वपूर्ण स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नर्सिंग क्षेत्र में रोजगार और सेवा के व्यापक अवसर उपलब्ध हैं, उन्होंने कहा कि मनेन्द्रगढ़ में नर्सिंग महाविद्यालय भवन बनने से जिले एवं आसपास के क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्तापूर्ण नर्सिंग शिक्षा के लिए बड़े शहरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा,उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर चिकित्सा शिक्षा की उपलब्धता से आर्थिक रूप से कमजोर एवं ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को विशेष लाभ मिलेगा।

मुख्य बिंदु...

- मनेन्द्रगढ़ नर्सिंग महाविद्यालय भवन निर्माण हेतु 868.35 लाख स्वीकृत
- चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जारी की प्रशासनिक स्वीकृति
- स्थानीय युवाओं को घर के पास नर्सिंग शिक्षा का अवसर
- स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा प्रशिक्षित मानव संसाधन
- दूरस्थ क्षेत्रों तक चिकित्सा शिक्षा पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
- स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जताया आभार...

स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा नया आधार

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नर्सिंग शिक्षा केवल रोजगार का माध्यम नहीं बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ है,प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता से अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की कार्यक्षमता बढ़ेगी तथा आम नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होंगी,उन्होंने कहा कि इस महाविद्यालय के माध्यम से भविष्य में क्षेत्र को प्रशिक्षित नर्सिंग मानव संसाधन उपलब्ध होगा,जिससे स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में मदद मिलेगी।

दूरस्थ अंचलों तक चिकित्सा शिक्षा पहुंचाने का संकल्प

श्री जायसवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य केवल बड़े शहरों तक चिकित्सा शिक्षा सीमित रखना नहीं है,बल्कि दूरस्थ और आदिवासी अंचलों तक भी इसकी पहुंच सुनिश्चित करना है,मनेन्द्रगढ़ में नर्सिंग महाविद्यालय भवन निर्माण की स्वीकृति इसी सोच और संकल्प का परिणाम है, उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है,ताकि युवाओं को अपने क्षेत्र में ही बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकें।

एमसीबी जिले के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि

मनेन्द्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी जिले के गठन के बाद लगातार नई संस्थाओं और अधोसंरचनात्मक परियोजनाओं को स्वीकृति मिल रही है,नर्सिंग महाविद्यालय भवन निर्माण के लिए मिली यह स्वीकृति जिले के शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है,विशेषज्ञों का मानना है कि महाविद्यालय के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद न केवल जिले के विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा,बल्कि आसपास के कोरिया,सूरजपुर और सरगुजा संभाग के अन्य क्षेत्रों के छात्रों को भी इसका फायदा मिलेगा।

CMYK

नौगई तिहरे हत्याकांड पर भूपेश बघेल का बड़ा हमला,

- बोले— यह सामान्य विवाद नहीं, सुनियोजित नृशंस हत्या
- नौगई पहुंचे भूपेश बघेल, पीड़ित परिवारों से मिले, सीबीआई जांच और पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग
- तीन लोगों को जिंदा जलाना सामान्य घटना नहीं— नौगई में भूपेश बघेल ने उठाए जांच पर सवाल
- नौगई हत्याकांड में राजनीतिक संरक्षण का आरोप, भूपेश बोले— सच्चाई सामने लाने सीबीआई जांच जरूरी
- पीड़ित परिवारों के बीच पहुंचे भूपेश बघेल, कहा— न्याय मिलने तक लड़ाई में साथ रहूंगा
- नौगई हत्याकांड: पुलिस, राजनीति और संरक्षण पर उठे सवाल, भूपेश बघेल ने मांगी निष्पक्ष जांच
- नौगई में न्याय की मांग के बीच भूपेश का सरकार पर वार, बोले— संरक्षण के बिना इतनी नृशंसता संभव नहीं
- हम न्याय चाहते हैं— नौगई के पीड़ित परिवारों का दर्द सुन भावुक हुए भूपेश बघेल
- नौगई तिहरे हत्याकांड में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की एंट्री
- सीबीआई जांच, पुलिस कार्रवाई और राजनीतिक संरक्षण के आरोपों को लेकर उठाए बड़े सवाल

-रवि सिंह-

कोरिया/सोनहत,24 जून 2026 (घटती-घटना)। कोरिया जिले के सोनहत थाना क्षेत्र अंतर्गत नौगई गांव में 16 और 17 जून की दरमियानी रात हुए तिहरे हत्याकांड को लेकर प्रदेश की राजनीति लगातार गरमाती जा रही है,इसी क्रम में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पीड़ित परिवारों से मिलने नौगई पहुंचे,उन्होंने मृतकों के घर पहुंचकर उनके छायाचित्रों पर पुष्प अर्पित किए,श्रद्धांजलि दी और परिजनों से लंबी चर्चा कर घटना से जुड़े पहलुओं की जानकारी ली।

मुलाकात के दौरान का माहौल बेहद भावुक रहा,परिजनों ने रोते-बिलखते हुए घटना की पूरी आपबीती पूर्व मुख्यमंत्री को बताई। कई परिजन न्याय व्यवस्था और पुलिस कार्रवाई को लेकर अपनी आशंकाएं भी व्यक्त करते नजर आए, भूपेश बघेल ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए भरोसा दिलाया कि उनकी लड़ाई केवल एक परिवार की नहीं बल्कि न्याय की लड़ाई है और वह इस मुद्दे को हर मंच पर उठाएंगे। पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उपलब्ध तथ्यों और परिजनों के बयानों को देखने-सुनने के बाद यह घटना किसी सामान्य झगड़े या आपसी विवाद का परिणाम नहीं लगती,उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को जिंदा जलाकर मार देना अत्यंत नृशंस और अमानवीय कृत्य है, इस तरह की घटना समाज को झकझोर देने वाली है और इसकी जांच भी उसी गंभीरता के साथ होनी चाहिए,उन्होंने कहा कि एक सामान्य व्यक्ति भी घटना की परिस्थितियों को देखकर कई सवाल खड़े कर सकता है, लेकिन यदि जांच एजेंसियां उन सवालों को नजरअंदाज करें तो स्वाभाविक रूप से संदेह पैदा होता है।

विधानसभा से सड़क तक लड़ाई लड़ने का संकेत

भूपेश बघेल ने स्पष्ट किया कि वह इस पूरे मामले को विधानसभा में उठाएंगे और सरकार से जवाब मांगेंगे, उन्होंने कहा कि यह केवल एक गांव या एक परिवार का मामला नहीं बल्कि कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता से जुड़ा प्रश्न है, उन्होंने कहा कि जब तक पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक इस मामले को लेकर आवाज उठती रहेगी।

सीबीआई जांच की मांग को बताया उचित

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पीड़ित परिवार जिस प्रकार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं,वह पूरी तरह उचित है,उन्होंने कहा कि जब किसी मामले में राजनीतिक संरक्षण,प्रभावशाली लोगों की भूमिका और जांच को प्रभावित करने जैसे आरोप सामने आते हैं,तब निष्पक्षता बनाए रखने के लिए स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराना जरूरी हो जाता है,उन्होंने कहा कि इस मामले में सीबीआई जांच से ही लोगों का विश्वास बहाल हो सकेगा और यह स्पष्ट हो सकेगा कि घटना के पीछे वास्तविक कारण क्या थे तथा किन लोगों की भूमिका रही।

जिम्मेदारी तय होनी चाहिए...

भूपेश बघेल ने कहा कि केवल आरोपियों की गिरफ्तारी पर्याप्त नहीं है,यह भी देखना आवश्यक है कि घटना से पहले और बाद में पुलिस तथा प्रशासन की भूमिका क्या रही,उन्होंने मांग की कि घटना के समय जिले में जिम्मेदारी संभाल रहे तत्कालीन पुलिस अधीक्षक और स्थानीय थाना प्रभारी की भूमिका की भी समीक्षा की जाए,यदि कहीं लापरवाही या पक्षपात सामने आता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए,उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं में जवाबदेही तय किए बिना न्याय की प्रक्रिया अधूरी रहती है।

पुलिस जांच पर उठाए कई सवाल...

पूर्व मुख्यमंत्री ने पुलिस की जांच प्रक्रिया को लेकर कई गंभीर प्रश्न उठाए,उन्होंने कहा कि घटना के शुरुआती दौर में पुलिस की ओर से अलग-अलग तरह की बातें सामने आईं, कभी घटना के कारणों को लेकर अलग संकेत मिले तो बाद में दूसरी बातें सामने आईं,उन्होंने कहा कि यदि जांच की दिशा स्पष्ट और तथ्यपरक होती तो इतने विरोधाभास सामने नहीं आते,यही कारण है कि लोगों के मन में संदेह पैदा हो रहा है,उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस द्वारा एक पक्ष के वाहनों की जांच किए जाने और दूसरे पक्ष को लेकर समान गंभीरता दिखाई गई या नहीं,यह भी जांच का विषय होना चाहिए।

गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ पर भी सवाल

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बाद में गिरफ्तार किए गए कुछ आरोपियों को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में है, उन्होंने पूछा कि जिन लोगों की गिरफ्तारी बाद में हुई, उनसे विस्तृत पूछताछ और रिमांड की आवश्यकता क्यों महसूस नहीं की गई? यदि किसी बड़ी साजिश की आशंका है तो आरोपियों से गहन पूछताछ कर पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया जाना चाहिए था, उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों को जल्दबाजी से बचते हुए हर पहलू की बारीकी से जांच करनी चाहिए।

स्थानीय विधायक को लेकर भी उठी नाराजगी...

घटना के दौरान और बाद में स्थानीय विधायक की भूमिका को लेकर भी चर्चा होती रही है,पूर्व मुख्यमंत्री के सामने परिजनों ने खुलकर अपनी नाराजगी व्यक्त की,परिजनों ने आरोप लगाया कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद उन्हें अपेक्षित संवेदना और सहयोग नहीं मिला,उन्होंने स्थानीय विधायक की भूमिका और कथित प्रभाव को लेकर भी जांच की मांग की, भूपेश बघेल ने कहा कि जनता के बीच जो सवाल उठ रहे हैं,उनका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से दिया जाना चाहिए,उन्होंने कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि का पहला दायित्व पीड़ित परिवारों के बीच पहुंचकर उनका दुख साझा करना होता है।

घटना में राजनीतिक षड्यंत्र के आरोप गंभीर

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना को लेकर राजनीतिक षड्यंत्र और संरक्षण जैसे आरोप भी सामने आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि ऐसे आरोपों को हल्के में नहीं लिया जा सकता, उन्होंने कहा कि यदि किसी अपराध के पीछे राजनीतिक प्रभाव या संरक्षण की बात कही जा रही है तो उसकी स्वतंत्र जांच होना और भी जरूरी हो जाता है, उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच ही इन आरोपों की सच्चाई सामने ला सकती है।

परिजनों ने कहा—न्याय नहीं मिला तो करेंगे बड़ा आंदोलन

पूर्व मुख्यमंत्री की मौजूदगी में पीड़ित परिवारों ने अपनी पीड़ा खुलकर रखी, कई परिजनों ने कहा कि उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर भय है और उन्हें आशंका है कि कहीं मामले को कमजोर करने का प्रयास न हो, परिजनों ने कहा कि यदि उन्हें निष्पक्ष जांच और न्याय नहीं मिला तो वे बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे, कुछ परिजनों ने सामूहिक आत्मदाह जैसी चेतावनी तक दे डाली, जिसे सुनकर वहां मौजूद लोग भी भावुक हो गए, पूर्व मुख्यमंत्री ने परिजनों से संयम बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि न्याय के लिए संवैधानिक और लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ी जानी चाहिए।

अब क्या?

नौगई तिहरे हत्याकांड में अब तक कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है,लेकिन घटना की भयावहता,राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप,पुलिस जांच पर उठते सवाल और पीड़ित परिवारों की नाराजगी ने इस मामले को प्रदेश के सबसे चर्चित मामलों में ला खड़ा किया है,पूर्व मुख्यमंत्री की नौगई यात्रा के बाद यह मामला और अधिक राजनीतिक एवं सामाजिक बहस का केंद्र बन गया है, अब देखना होगा कि सरकार,पुलिस प्रशासन और जांच एजेंसियां उठ रहे सवालों का जवाब किस प्रकार देती हैं और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ती है।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने हुई लाखों की चोरी का खुलासा,तीन नाबालिगों से चोरी का सामान बरामद

9 लाख से अधिक की संपत्ति हुई थी चोरी,सीसीटीवी और मुखबिर सूचना से पुलिस को मिली सफलता

-संवाददाता-

कोरिया/बैकुंठपुर,24 जून 2026 (घटती-घटना)। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने स्थित सिविल लाइन आवासीय परिसर में हुई लाखों रुपये की चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए तीन नाबालिगों को पकड़ने में सफलता हासिल की है,पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी गया आईपैड,मोबाइल फोन, घड़ियां सहित करीब 1.20 लाख रुपये मूल्य का सामान बरामद किया है, वहीं मामले के दो अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं,जिनकी तलाश जारी है।

न्यायाधीश के आवास में हुई थी चोरी- जानकारी के अनुसार 4 जून 2026 को द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश प्रेरणा अहिरे ने बैकुंठपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके आवास से सोने-चांदी के आभूषण, मोबाइल फोन, आईपैड,घड़ियां एवं अन्य कीमती सामान चोरी हो गया है,चोरी गई संपत्ति का कुल मूल्य लगभग 9 लाख 7 हजार रुपये बताया गया था,शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 177/26 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की।

सीसीटीवी फुटेज और जैकेट बना अहम सुराग- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. सुरेशा चौबे के निर्देशन एवं एसडीओपी राजेश साहू के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने मामले की जांच शुरू की, घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए, जांच के दौरान घटनास्थल से एक सफेद रंग का जैकेट भी बरामद किया गया,जिसे महत्वपूर्ण साक्ष्य माना गया,पुलिस ने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया और लगातार संदिग्धों की गतिविधियों पर नजर रखी,इसी दौरान सूरजपुर जिले के तीन नाबालिगों पर संदेह गहराया।

पूछताछ में कबूला चोरी का अपराध- पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने पर तीनों नाबालिगों ने चोरी की वारदात में अपनी संलिप्तता स्वीकार की, पूछताछ में यह भी सामने आया कि उन्होंने ऋषभ उर्फ रिशु यादव एवं आयुष रजक के साथ मिलकर पुलिस कार्यालय के सामने स्थित मकान का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया था,आरोपियों ने घर में घुसकर सोने-चांदी के आभूषण,मोबाइल फोन, घड़ियां और आईपैड चोरी करना स्वीकार किया।

चोरी का सामान बरामद- पुलिस ने नाबालिग आरोपियों के कब्जे से एक ओप्पो मोबाइल, एक नारजो मोबाइल, दो घड़ियां और एक आईपैड सहित लगभग 1 लाख 20 हजार रुपये मूल्य का सामान बरामद किया है, बरामदगी के बाद पुलिस ने तीनों नाबालिगों को 18 जून 2026 को गिरफ्तार कर किशोर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

दो आरोपी अब भी फरार- पुलिस के अनुसार मामले में शामिल दो अन्य आरोपी ऋषभ उर्फ रिशु यादव और आयुष रजक अभी फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है और पुलिस को उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

पुलिस टीम की रही अहम भूमिका- पूरे मामले के खुलासे में उप निरीक्षक राजेश तिवारी,उप निरीक्षक महेश कुशवाहा, आरक्षक समीर जायसवाल,दिनेश उइके तथा साइबर सेल बैकुंठपुर की महत्वपूर्ण भूमिका रही, पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच अभी जारी है और चोरी गए शेष सामान की बरामदगी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

पर्यावरण संरक्षण की अनूठी मिसाल, जन्मदिन पर स्वयंसेवक बिहारी लाल ने किया पौधारोपण

-संवाददाता-

कोरिया/बैकुंठपुर,24 जून 2026 (घटती-घटना)। जहां आजकल जन्मदिन मनाने का चलन केक, पार्टियों और दिखावे तक सीमित होता जा रहा है,वहीं राष्ट्रीय सेवा योजना (रा.से.यो.) के राज्य स्तरीय पुरस्कृत वरिष्ठ स्वयंसेवक बिहारी लाल साहू पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए अपने जन्मदिन को एक नई पहचान दे रहे हैं। कोविड-19 काल से शुरू की गई उनकी यह पहल अब समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है।

बिहारी लाल साहू प्रत्येक वर्ष अपने जन्मदिन के अवसर पर पौधारोपण कर प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं,उनका मानना है कि पौधे लगाना केवल आज की आवश्यकता नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य के लिए हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। वर्तमान में वे के.बी. पटेल महाविद्यालय, सरभोका में बीएड चतुर्थ सेमेस्टर के छात्राध्यापक हैं और शिक्षा के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना की विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उन्होंने युवाओं और ग्रामीणों को पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और सामाजिक सरोकारों के प्रति जागरूक करने का कार्य किया है। अपने जन्मदिन पर लगाए गए पौधों का संरक्षण भी वे स्वयं करते हैं,जिससे यह पहल केवल औपचारिकता बनकर नहीं रह जाती बल्कि पर्यावरण संवर्धन का एक स्थायी प्रयास बन जाती है, इस अवसर पर बिहारी लाल साहू ने कहा कि प्रकृति और मानव जीवन का गहरा संबंध है, यदि आज हम पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ और अन्य विशेष अवसरों पर पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण में योगदान दें, उनकी यह पहल समाज को सकारात्मक संदेश देने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर रही है।

साइंस से भी परे हैं मिथुन चक्रवर्ती की इस फिल्म के फाइट सीन

28 साल बाद भी वैज्ञानिक नहीं समझ पाए लॉजिक

मिथुन चक्रवर्ती की 1998 में एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई थी,जिसमें ऐसे अनोखे फाइट सीन फिल्माए गए थे, जो साइंस से भी परे हैं, जिसे देखने के बाद दर्शक भी अपने बाल नोचने पर मजबूर हो जाएंगे। 70 और 80 के दशक के मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों में उनका डांस तो दर्शकों को काफी पसंद आता ही था, लेकिन इसके साथ ही उनकी मूवीज के एक्शन सीक्वेंस से लेकर दमदार डायलॉग्स भी खूब वायरल होते थे और उन पर मीम्स बनते थे। 28 साल पहले मिथुन चक्रवर्ती की एक ऐसी फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जो साइंस की समझ से परे हैं और आज की जेन-जी की भी,क्योंकि उसमें ऐसे सीन फिल्माए गए है,जिनके पीछे ने निर्देशक ने क्या लॉजिक लगाया है, यह पता लगाना बेहद मुश्किल है।

गुंडों को एक मक्के में बहा खून,पर मिथुन को नहीं आई चोट

मिथुन चक्रवर्ती की जिस फिल्म का जिक्र हम अपने इस लेख में कर रहे हैं, वह साल 1998 में रिलीज हुई गुंडा थी,जिसमें कई फाइट सीक्वेंस ऐसे थे, जिसको लेकर इंटरनेट पर कई मीम बने। फिल्म का सबसे पहला सीन है,जब एक पुलिस ऑफिसर को कुछ गुंडे मारते हैं और मिथुन चक्रवर्ती अचानक वहां पर आते हैं। एक गुंडा तेजी से उछलता है और मिथुन उसे एक मुक्के में हवा में ही ढेर कर देते हैं। वहीं इसी सीन के अंदर मिथुन दो गुंडों को मुक्का मारते हैं और वह जमीन पर गिरने की बजाय सीधा छत पर जाकर खड़े हो जाते हैं। एक सीन में मिथुन चक्रवर्ती खुद गुंडों को लातों-घूसों से मारते हुए हवा में तैरते हैं। सभी गुंडे ढेर हो जाते हैं, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती को चोट तक नहीं आती है।

साइकिल के पीछे छुपकर चलाई गोलियां

फिल्म में एक और सीन है, जहां पुलिस का काफिला नेता को लेकर जा रहा है और पहले ऑटो में बैठकर वह कार पर खुलेआम निशाना साध रहे हैं, लेकिन पुलिस ऑफिसर उन्हें नहीं देख पा रहा है। इसके बाद वह साइकिल के पीछे छुपकर निशाना साधते हैं। पुलिस वालों को शंकर तब भी नहीं दिखता। पतले से खम्बे के पीछे जाकर फिर से वह निशाना साधता है,लेकिन तीन बार गोली की आवाज सुनकर भी पुलिस बेसुध होती है।
जब अंत में मिथुन का एक निशाना लगता है और नेता की गाड़ी पलट जाती है, तो पुलिस मिथुन को देखती है और उसके पीछे भागती है। वह भागते-भागते रेगिस्तान में नेता को पकड़ लेता है,लेकिन पास पहुंचकर भी पुलिस पीछे हाथ बांधे खड़ी रहती है। इस सीन पर उस समय पर काफी मीम भी बने थे।

गाड़ी के उड़े परखच्चे...पीछे से निकला विलेन

कार में तो अक्सर खड़े-खड़े आग लग जाती हैं,लेकिन वैज्ञानिकों को मूवी का एक सीन देखकर सच में अपने बाल नोंचने का मन जरूर करेगा। ये सीन तब आता है जब गुंडा शंकर जेल से छूटने के बाद नेता से बहन की मौत का बदला लेता है। शंकर का निशाना नेता की कार के टायर पर लगता है और गाड़ी बुरी तरह घूमते-घूमते काफी खराब हो जाती है, लेकिन मजाल है कि फिल्म के विलेन को कुछ हो जाए। सीन में दिखाया गया है कि कैसे इतनी बड़ी गाड़ी पलटने और बड़ी सड़क दुर्घटना के बावजूद विलेन बड़ी ही आसानी से कार के पीछे वाले दरवाजे से निकलता है और रेत की तरफ भागता है।

डायलॉग मारते-मारते की गुंडों की कुटाई

डायलॉग बोलना और गुंडों की पिटाई करना यह काम सिर्फ मिथुन चक्रवर्ती ही कर सकते हैं। गुंडा में मिथुन का कैरेक्टर धुनाई करते-करते भी अपने डायलॉग भूलता नहीं है, वह ऐसे-ऐसे भारी-भरकम डायलॉग बोलता है, जिसे देखकर भेजा फ्राई हो जाएगा।
इसमें एक सीन ऐसा भी है,जहां विलेन बने मुकेश ऋषि पूरे गुंडों की फौज लेकर ऑटो में रेगिस्तान में आते हैं। वह छोटी बन्दूक नहीं,बल्कि बड़ी राइफल से शंकरपर वार करते हैं, लेकिन मजाल है कि एक भी गोली ने उसे छू लिया हो,जबकि उसकी एक मिसाइल से बहुत दूर से आ रहे ऑटो की धज्जियां उड़ जाती हैं। खैर अगर आप मिथुन चक्रवर्ती की इस अनोखी फिल्म को देखना चाहते हैं,तो गुंडा आपको यू-ट्यूब पर मिल जाएगी।

न संगीता बिजलानी,ना सोमी...कौन थीं सलमान खान की पहली गर्लफ्रेंड? कियारा आडवाणी से है गहरा कनेक्शन

सलमान खान की पहली गर्लफ्रेंड शाहीन जाफरी थीं,जिनका एक्ट्रेस कियारा आडवाणी से खास कनेक्शन है। सलमान ने 19 साल की उम्र में शाहीन को डेट करना शुरू किया था। सलमान खान की लव लाइफ हमेशा से ही मीडिया में चर्चा का विषय रही है। सलमान खान ने अपनी यंग ऐज में कई एक्ट्रेस को डेट किया जिसमें संगीता बिजलानी और सोमी अली आदि का नाम आता है।

क्या है कियारा आडवाणी से कनेक्शन?

लेकिन क्या आपको पता है कि इन सबसे भी पहले सलमान खान किस के साथ सीरियस रिलेशनशिप में थे और इसका कियारा आडवाणी के साथ खास कनेक्शन है। खबरों के अनुसार, सलमान मशहूर एक्टर अशोक कुमार की पोती शाहीन जाफरी के साथ सीरियस रिलेशन था। दिलचस्प बात यह है कि शाहीन एक्ट्रेस

कियारा आडवाणी की मौसी लगती हैं।

19 साल की उम्र से कर रहे डेट

कई मीडिया रिपोर्ट्स और 2018 में स्पॉटबॉय को दिए भारती जाफरी के एक पुराने इंटरव्यू के अनुसार, सलमान खान और शाहीन जाफरी एक-दूसरे के प्यार में थे। कहा जाता है कि जब उन्होंने एक-दूसरे को डेट करना शुरू किया, तब सलमान लगभग 19 साल के थे। शाहीन मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ती थीं और कहा जाता है कि सलमान सिर्फ उन्हें देखने के लिए घंटों कॉलेज कैंपस के बाहर इंतजार करते थे।

लंबा नहीं चला रिलेशन

दोनों ने लगभग कुछ समय के लिए डेट किया लेकिन इनका रिलेशन लंबा नहीं चला। बॉलीवुड में एंट्री करने के बाद सलमान खान की मुलाकात संगीता बिजलानी से हुई और शाहीन से उनका ब्रेकअप हो गया। एक इंटरव्यू में कियारा आडवाणी ने भी ये बात स्वीकार की थी। शाहीन की बहन जेनेवीव, कियारा की मां हैं। कियारा ने बताया था कि सलमान ने उनके डेब्यू के समय उन्हें मेंटोर किया था।
सलमान के साथ अपना रिश्ता खत्म करने के बाद, शाहीन ने एविएशन के क्षेत्र में करियर बनाया। यहां उनकी मुलाकात बिजनेसमैन विक्रम अग्रवाल से हुई। दोनों ने 1994 में शादी की और उनके दो बच्चे हैं - बेटा निर्वाण और बेटी नाद्या हैं।

इस हफ्ते ओटीटी पर किसका जलवा रहा

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हर हफ्ते दर्जनों नई फिल्में, वेब सीरीज,रियलिटी शो और स्टैंड-अप कॉमेडी कंटेंट रिलीज होते हैं,लेकिन इनमें से कुछ ही दर्शकों के बीच खास जगह बना पाते हैं। इसी बीच ऑरमैक्स मीडिया ने 15 से 21 जून के बीच सबसे ज्यादा देखे गए ओटीटी कंटेंट की नई लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर इंडियाज गॉट लेटेंट है, जिसे कॉमेडियन समय रैना होस्ट करते हैं। यह शो हाल ही में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया गया है और यूट्यूब पर भी इसे बड़ी संख्या में दर्शक देख रहे हैं। अपनी अलग और अनोखी कॉमेडी स्टाइल के कारण यह शो लगातार चर्चा में बना हुआ है।
दर्शकों के बीच इस शो की लोकप्रियता का कारण इसका अनफिल्टर्ड और इंटरैक्टिव फॉर्मेट बताया जा रहा है, जिसमें कंटेस्टेंट्स और जजेस के बीच मजेदार बातचीत देखने को मिलती है। यही वजह है कि यह शो इस हफ्ते ओटीटी ट्रेंडिंग लिस्ट में टॉप पर पहुंच गया है। ओटीटी पर दूसरी पोजिशन पर एक चर्चित वेब सीरीज और तीसरे स्थान पर एक थ्रिलर कंटेंट रहा, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया। लिस्ट में अन्य स्थानों पर भी कई फिल्में और सीरीज शामिल हैं, जो अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो और डिज्नी+ हॉटस्टार पर उपलब्ध हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट की बढ़ती संख्या के बावजूद दर्शक अब सिर्फ वही चुन रहे हैं जो उन्हें मनोरंजन के साथ कुछ नया अनुभव दे। यही कारण है कि हर हफ्ते ट्रेंडिंग लिस्ट में बदलाव देखने को मिलता है। 'इंडियाज गॉट लेटेंट' की बढ़ती लोकप्रियता यह भी दिखाती है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर स्टैंड-अप और रियलिटी कॉमेडी शो का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। समय रैना की अनोखी होस्टिंग स्टाइल ने इस शो को युवाओं के बीच खास बना दिया है। कुल मिलाकर, इस हफ्ते ओटीटी की ट्रेंडिंग लिस्ट में कॉमेडी और रियलिटी कंटेंट का दबदबा देखने को मिला है, जो दर्शकों की बदलती पसंद को भी दर्शाता है।

रणबीर कपूर कटरीना कैफ का रिश्ता फिर सुर्खियों में

बॉलीवुड के चर्चित कपल रहे रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ एक समय इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले रिश्तों में से एक थे। दोनों ने साल 2009 के आसपास एक-दूसरे को डेट करना शुरू किया था और कई सालों तक उनका रिश्ता सुर्खियों में बना रहा। हालांकि, साल 2016 में दोनों का ब्रेकअप हो गया और इसके बाद दोनों ने अपनी-अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हुए नए पार्टनर्स के साथ जीवन की नई शुरुआत की। रणबीर कपूर आज आलिया भट्ट के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे हैं, जबकि कैटरीना कैफ ने विक्की कौशल के साथ शादी कर ली है। इसी बीच एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट विकी लालवानी के एक पुराने बयान ने फिर से इस चर्चित रिश्ते को चर्चा में ला दिया है। उन्होंने बताया कि एक समय पर ब्रेकअप के बाद कैटरीना कैफ ने उनसे बातचीत में कहा था कि अगर रणबीर कपूर चाहेंगे, तो वह उनके पास वापस जाने के लिए तैयार थीं। इस खुलासे के बाद एक बार फिर दोनों के पुराने रिश्ते को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, समय के साथ दोनों ने अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया और अपने-अपने करियर और निजी जीवन पर ध्यान दिया। फिल्म इंडस्ट्री में रणबीर और कैटरीना की जोड़ी को लेकर हमेशा ही दर्शकों में काफी दिलचस्पी रही है। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को भी काफी पसंद किया गया। आज दोनों अपनी-अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन उनका पुराना रिश्ता और उससे जुड़े किस्से समय-समय पर सुर्खियों में आ ही जाते हैं।

खेल समाचार

क्रिकेट मैदान पर आशीर्वाद की शानदार बल्लेबाजी

नई दिल्ली,24 जून 2026। भारतीय क्रिकेट में एक बार फिर युवा प्रतिभाओं की चर्चा तेज हो गई है। वैभव सूर्यवंशी,जिन्हें देश का उभरता हुआ क्रिकेट स्टार माना जा रहा है, अब इंटरनेशनल डेब्यू के लिए तैयार हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि आयरलैंड के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज में उन्हें भारतीय टीम की ओर से डेब्यू का मौका मिल सकता है।

इस खबर के बीच उनके परिवार से भी एक बड़ी क्रिकेट उपलब्धि सामने आई है, जिसने सभी का ध्यान खींच लिया है। वैभव सूर्यवंशी के छोटे भाई आशीर्वाद सूर्यवंशी ने हाल ही में अपने शानदार प्रदर्शन से क्रिकेट जगत को चौंका दिया है। एक लोकल क्रिकेट मैच में खेलते हुए आशीर्वाद ने तूफानी बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और 119 गेंदों पर 168 रन की विस्फोटक पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 19 चौके और 6 लंबे छक्के लगाए, जिससे उनकी बल्लेबाजी की आक्रामक शैली साफ दिखाई दी। सबसे खास बात यह है कि आशीर्वाद सूर्यवंशी की उम्र मात्र 10 साल बताई जा रही है। इतनी कम उम्र में इस तरह का बड़ा स्कोर बनाना क्रिकेट प्रेमियों के लिए आश्चर्य का विषय बन गया है। उनकी इस पारी ने स्थानीय क्रिकेट से लेकर सोशल मीडिया तक हलचल मचा दी है, और लोग उनकी तुलना बड़े खिलाड़ियों की शैली से करने लगे हैं।

न्यूजीलैंड ने स्कॉटलैंड को हराकर दर्ज की लगातार दूसरी जीत

नई दिल्ली,24 जून 2026। महिला टी-20 विश्व कप 2026 के 19वें मुकाबले में न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम ने स्कॉटलैंड महिला क्रिकेट टीम को 6 विकेट से हरा दिया। ये कीवी टीम की इस टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत है। वहीं, पहले 2 मैच में उसने वेस्टइंडीज और श्रीलंका के खिलाफ हार झेली थी। स्कॉटलैंड ने लगातार तीसरी हार झेली है। उसे एकमात्र जीत आयरलैंड के खिलाफ अपने पहले मैच में मिली थी। मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। स्कॉटलैंड की टीम 20 ओवर में 131/7 का स्कोर ही बना पाई। डार्सी कार्टर ने स्कॉटलैंड के लिए सबसे ज्यादा 72 रन की पारी खेली। उनके अलावा और कोई भी बल्लेबाज अच्छा नहीं कर पाया। अमेलिया केर ने 3

विकेट अपने नाम किए। जवाब में न्यूजीलैंड ने 18.2 ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इजी शार्प ने सबसे ज्यादा 62 रन की पारी खेली। कार्टर ने 52 गेंदों का सामना किया और 72 रन बनाकर आउट हुईं। उनके बल्ले से 8 चौके और एक छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 138.46 की रही। कार्टर ने इस टूर्नामेंट में अपना दूसरा पचासा लगाया। उन्होंने अब तक 8 मुकाबले खेले हैं और इसकी 8 पारियों में 32.16 की औसत से 193 रन बनाने में सफल रहीं हैं।

ब्राजील से लेकर मेक्सिको तक, फीफा वर्ल्ड कप में आज भिड़ेंगी 12 टीमें

फीफा विश्व कप 2026 के ग्रूप चरण में रोमांच अपने चरम पर पहुंच चुका है...25 जून के दिन टूर्नामेंट में 6 मुकाबले खेले जाने वाले हैं। ब्राजील, मेक्सिको और मोर क्को जैसी धाकड़ टीमें मैदान पर होने वाली हैं...

नई दिल्ली,24 जून 2026। फीफा विश्व कप 2026 के ग्रूप चरण में रोमांच अपने चरम पर पहुंच चुका है। 25 जून की सुबह टूर्नामेंट में 6 अहम मुकाबले लेकर आने वाली है। जिनके बाद ग्रूप ए, बी और सी की अंतिम स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कई टीमों की नॉकआउट में जगह लगभग तय है, जबकि कुछ टीमों के लिए यह करो या मरो का मुकाबले होंगे।

स्विट्जरलैंड बनाम कनाडा (रात 12:30 बजे)

ग्रूप सी का यह सबसे बड़ा मुकाबला माना जा सकता है।। दोनों टीमों के चार-चार अंक हैं और विजेता टीम ग्रूप में शीर्ष स्थान हासिल कर सकती है। कनाडा ने पिछले मैच में कतर को 6-0 से

हराकर शानदार फॉर्म दिखाई थी। वहीं स्विट्जरलैंड ने बोस्निया एवं हर्जेगोविना को 4-1 से हराकर आत्मविश्वास बढ़ाया है। दोनों टीमों का आक्रमण मजबूत दिखा है। इसलिए यह मुकाबला काफी रोमांचक रहने की उम्मीद है।

बोस्निया और हर्जेगोविना बनाम कतर (रात 12:30 बजे)

बोस्निया और हर्जेगोविना बनाम कतर मैच में दोनों टीमें एक-एक अंक के साथ उतरने वाली हैं। नॉकआउट में जाने की उम्मीदें जिंदा रखने के लिए दोनों को जीतना जरूरी है। कतर को पिछले मैच में कनाडा के हाथों 0-6 की करारी हार मिली थी, जिससे टीम का मनोबल प्रभावित हुआ है। दूसरी ओर बोस्निया भी स्विट्जरलैंड के खिलाफ4-1 से बड़ी हार झेल चुका है। ऐसे में दोनों टीमें जीत के साथ टूर्नामेंट में बने रहने की कोशिश करेंगी।

मोरक्को बनाम हैती (सुबह 3:30 बजे)

मोरक्को शानदार लय में है और चार अंकों के साथ ग्रूप सी में शीर्ष स्थान की दौड़ में बनी हुई है। टीम ने स्कॉटलैंड को 1-0 से हराकर अपनी मजबूती साबित की थी। दूसरी ओर हैती लगातार दो मैच हार चुका है और टूर्नामेंट से लगभग बाहर हो चुका है। मौजूदा फॉर्म को देखते हुए मोरक्को इस मुकाबले को जीतने का प्रबल दावेदार है।

स्कॉटलैंड बनाम ब्राजील (सुबह 3: 30 बजे)

दिन का सबसे बड़ा मुकाबला ब्राजील और स्कॉटलैंड के बीच खेला जाएगा। ब्राजील चार अंकों के साथ मजबूत स्थिति में है और उसने पिछले मैच में हैती को 3-0 से हराया था। स्कॉटलैंड के तीन अंक हैं और उन्हें नॉकआउट की उम्मीदें बनाए रखने के लिए कम से कम एक अंक की जरूरत पड़ सकती है। ब्राजील की स्टार खिलाड़ियों से सजी टीम को जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है।

दक्षिण अफ्रीका बनाम दक्षिण कोरिया (सुबह 6:30 बजे)

ग्रूप ए में दक्षिण कोरिया तीन अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। जबकि दक्षिण अफ्रीका के पास केवल एक अंक है। दक्षिण कोरिया ने टूर्नामेंट में अच्छा खेल दिखाया है। इस मुकाबले में जीत या ड्रॉ उनके लिए नॉकआउट के दरवाजे खोल सकती है। दक्षिण अफ्रीका को नॉकआउट की उम्मीदें कायम रखने के लिए हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी।

चेक रिपब्लिक बनाम मेक्सिको (सुबह 6: 30 बजे)

मेक्सिको लगातार दो जीत के साथ शानदार फॉर्म में है और छह अंकों के साथ ग्रूप ए में शीर्ष पर है। टीम ने दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण कोरिया दोनों को हराया है। दूसरी ओर चेक रिपब्लिक के पास केवल एक अंक है और उसे जीत की सख्त जरूरत है। मेक्सिको का आत्मविश्वास और वर्तमान फॉर्म उसे इस मुकाबले का सबसे मजबूत दावेदार बना देता हैं।

अल्जीरिया ने जॉर्डन को हराया

नईदिल्ली,24 जून 2026। फीफा विश्व कप 2026 में ग्रूप-जे में खेले गए एक अहम मुकाबले में अल्जीरिया ने जॉर्डन को 2-1 से हरा दिया। इसके साथ उसने अपनी नॉकआउट में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखा है। अब तीसरे मैच के परिणाम के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। मैच में 0-1 से पिछड़ने के बाद अल्जीरिया ने शानदार वापसी की और लगातार 2 गोल करते हुए मैच को अपने पक्ष में कर लिया। आइए इस मैच के रिकॉर्ड और आंकड़ों पर नजर डालते हैं। मैच के पहले हाफ में गेंद पर अल्जीरिया का दबदबा था, लेकिन उसके खिलाड़ी जॉर्डन के मजबूत रक्षापंक्ति को भेदने में नाकाम रहे। जॉर्डन ने जवाबी हमले की रणनीति अपनाई और 36वें मिनट में उसे सफलता भी मिल गई। बॉक्स के अंदर मूसा अल-तामरी के एक गलत शॉट से गेंद निजार अल-रश्दान के पास आ गई। इस पर उन्होंने अपने पैर के बाहरी हिस्से से शानदार गोल करते हुए टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। पहले हाफ में 1 गोल से पिछड़ने के बाद अल्जीरिया ने दूसरे हाफ में आक्रामक खेल दिखाया। टीम ने जॉर्डन पर चौतरफा हमले किए और कुल 10 कॉर्नर किक हासिल कीं। अल्जीरिया ने इस दबाव का फायदा उठाया और 69वें मिनट में रियाद महरेज के पास पर स्थानापन्न नाधिर बेनबोआली ने बेहतरीन गोल कर टीम को बराबरी दिला दी।

CMYK

रायपुर में प्रदेश पदाधिकारियों की मीटिंग में फैसला....

बीजेपी आज 'काला दिवस' मनाएगी

रायपुर,24 जून 2026। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित भाजपा के प्रदेश कार्यालय 'कुशाभाऊ ठाकरे परिसर' में बुधवार को पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, संगठन महामंत्री पवन साय और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में चल रहे संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा करना और आने वाले समय के लिए पार्टी की भविष्य की रणनीति को अंतिम रूप देना था। भाजपा के संगठनात्मक ढांचे को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए इस बैठक में विभिन्न एजेंडों पर गहन विचार-विमर्श किया गया।

हर महीने की जाती है कार्यों की समीक्षा : किरण सिंह देव

बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने स्पष्ट किया कि पदाधिकारियों की यह बैठक एक नियमित प्रक्रिया है जो हर महीने आयोजित की जाती है। उन्होंने बताया कि इन बैठकों का मुख्य लक्ष्य पिछले कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना और भविष्य के लिए पार्टी के कार्यक्रमों की स्पष्ट रूपरेखा तैयार करना होता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा का लक्ष्य पार्टी द्वारा प्रांत स्तर पर लिए गए निर्णयों को जिला, मंडल और बूथ स्तर के 'शक्ति केंद्रों' तक बेहद प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करना है। भाजपा का संगठन साल के 365 दिन सक्रिय रहकर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं और आम जनता के साथ निरंतर संवाद बनाए रखता है।

आज भाजपा आपातकाल के विरोध में मनाएगी 'काला दिवस'

किरण सिंह देव ने जानकारी दी कि भाजपा आगामी 25 जून को पूरे प्रदेश में 'काला दिवस' के रूप में मनाएगी। इस दिन को देश के लोकतंत्र के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में याद किया जाता है, जब देश में आपातकाल लागू किया गया था। इस अवसर पर पार्टी मशाल जुलूस निकालेगी, रैलियां आयोजित करेगी और कई अन्य कार्यक्रम संपन्न किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को यह जानना बेहद आवश्यक है कि किस तरह आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक अधिकारों का गला घोंटा गया था और हजारों विपक्षी नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनता को लोकतंत्र की मजबूती और आपातकाल की विभीषिका के प्रति जागरूक करना है।

विपक्ष के आरोपों पर भाजपा का तीखा पलटवार : कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज द्वारा बैठक को लेकर दिए गए बयानों पर किरण सिंह देव ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि दीपक बैज को पार्टी की आंतरिक बैठक में हुई चर्चाओं के बारे में जानकारी कैसे हो सकती है, जबकि वे स्वयं उस बैठक का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता आधारहीन और भ्रामक बातें फैलाकर प्रदेश में एक गलत नैरेटिव गढ़ने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस अपनी हार की हताशा में इस तरह के बयान दे रही है, जिसका जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है।

बूथ स्तर तक सरकार की योजनाओं के प्रचार की रणनीति

सूत्रों के अनुसार, बैठक में सरकारी योजनाओं के सफल प्रचार-प्रसार और उन्हें राज्य के अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए ठोस रणनीति बनाई गई। आगामी संगठनात्मक अभियानों और जिलों में चल रही पार्टी की गतिविधियों को लेकर भी पदाधिकारियों को विशेष दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, ताकि प्रदेश के विकास की गति को और तेज किया जा सके। भाजपा का आगामी फोकस अब बूथ स्तर पर अपनी पकड़ को और अधिक मजबूत करने पर है।

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का बड़ा फैसला...

आंगनबाड़ी बहनों को मिली बड़ी राहत,अब साड़ी खरीदने के लिए सीधे खाते में आएगी राशि

रायपुर,24 जून 2026। छत्तीसगढ़ सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के हित में एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने साड़ी की केंद्रीकृत खरीद व्यवस्था को समाप्त करते हुए राशि सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में भेजने का निर्णय लिया है। इस फैसले को विभाग में पारदर्शिता बढ़ाने और कार्यकर्ताओं को अधिक अधिकार देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए साड़ियों की खरीद संचालनालय स्तर पर की जाती थी, लेकिन नई व्यवस्था के तहत साड़ी खरीद के लिए निर्धारित राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिए सीधे उनके खातों में पहुंचेगी। इससे वे अपनी पसंद और जरूरत के अनुसार साड़ी का चयन कर सकेंगी। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की सोच और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन मॉडल के अनुरूप लिया गया है। इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और सरकारी राशि का लाभ सीधे पात्र हितग्राहियों तक पहुंचेगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि साड़ी का रंग और डिजाइन पहले की तरह एक समान रखा जाएगा, ताकि पूरे प्रदेश में एकरूपता बनी रहे। अंतिम डिजाइन तय करने से पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं से भी सुझाव लिए जाएंगे।

साड़ी का निर्धारित डिजाइन विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि कपड़े के प्रकार का चयन स्थानीय स्तर पर स्वयं हितग्राही कर सकेंगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की बाल विकास सेवा योजना के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को हर वर्ष दो यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसके लिए प्रति यूनिफॉर्म अधिकतम 500 रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

छत्तीसगढ़ में अप्रैल से शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र,मई में मिलेगी गर्मी की छुट्टी

रायपुर,24 जून 2026। छत्तीसगढ़ में अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूलों का नया सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी शामिल हुए। वर्तमान में राज्य के स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र 16 जून से प्रारंभ होता है,लेकिन अब इसे सीबीएसई की तर्ज पर 1 अप्रैल से शुरू किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत अप्रैल माह में एक महीने तक नियमित कक्षाएं संचालित होंगी,जिसके बाद 1 मई से विद्यार्थियों को ग्रीष्मकालीन अवकाश दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के अनुसार अप्रैल में ही विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकें और गणवेश वितरित कर दिए जाएंगे। साथ ही सभी विषयों की पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी और छात्रों को गर्मी की छुट्टियों के लिए गृहकार्य भी दिया जाएगा। विभाग का मानना है कि इससे निर्धारित समय में पाठ्यक्रम पूरा करने में मदद मिलेगी और विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार आएगा।

डाटा अपडेट में लापरवाही पर होगी कार्रवाई

बैठक में शिक्षा मंत्री ने शासकीय विद्यालयों और जिला शिक्षा कार्यालयों द्वारा समय पर डाटा उपलब्ध नहीं कराए जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी जिला शिक्षा कार्यालय जून माह के अंत तक स्कूलों का आवश्यक डाटा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपडेट कराएं। निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं होने पर संबंधित प्राचार्यों और अधिकारियों के वेतन से कटौती की कार्रवाई की जा सकती है।

वीएसके ऐप से अनिवार्य होगी शिक्षकों की उपस्थिति

शिक्षकों की उपस्थिति अब वीएसके ऐप के माध्यम से दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐप के जरिए उपस्थिति दर्ज नहीं करने वाले शिक्षकों को अनुपस्थित माना जाएगा और उनके वेतन में कटौती की जा सकती है। अवकाश संबंधी आवेदन भी इसी ऐप के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे।

बुनियादी शिक्षा पर रहेगा विशेष जोर

बैठक में विद्यार्थियों की बुनियादी शैक्षणिक दक्षता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। निर्देश दिए गए कि प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को बारहखड़ी और 20 तक के पहाड़े तथा माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को 25 तक के पहाड़े याद हों। इसके अलावा हिंदी और अंग्रेजी में धाराप्रवाह पठन क्षमता विकसित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे।

छत्तीसगढ़ में मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल...

2 जुलाई से ग्रेड-पे और सामाजिक सुरक्षा की मांग

रायपुर,24 जून 2026। छत्तीसगढ़ में मनरेगा के तहत कार्यरत हजारों कर्मचारी एक बार फिर सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। अपनी लंबित मांगों के समर्थन में इन कर्मचारियों ने 2 जुलाई से प्रदेशभर में चरणबद्ध हड़ताल करने का ऐलान किया है। इस आंदोलन की घोषणा से राज्य के ग्रामीण विकास कार्यों और मनरेगा के तहत चल रही योजनाओं पर गहरा असर पड़ने की आशंका है। मनरेगा कर्मचारी संघ ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी महत्वपूर्ण मांगें पूरी नहीं की जातीं, वे अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। इस आंदोलन में राज्य के विभिन्न जिलों से 12 हजार से अधिक कर्मचारी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे।

चरणबद्ध होगा आंदोलन का स्वरूप : मनरेगा कर्मचारी संघ द्वारा जारी की गई कार्ययोजना के अनुसार, यह विरोध प्रदर्शन तीन चरणों में संपन्न होगा। आंदोलन की शुरुआत 2 जुलाई को जनपद स्तर से की जाएगी, जहां कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में एकजुट होंगे। इसके अगले दिन यानी 3 जुलाई को प्रदर्शन का दायरा बढ़ाकर जिला स्तर तक ले जाया जाएगा, जहां जिला मुख्यालयों पर सरकार को अपनी नाराजगी से अवगत कराया जाएगा। अंत में, 4 जुलाई को आंदोलन का समापन राज्य स्तरीय प्रदर्शन के रूप में होगा, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ से बड़ी संख्या में कर्मचारी रायपुर पहुंचेंगे। कर्मचारियों की यह संगठित रणनीति सरकार पर दबाव बनाने के लिए काफी मानी जा रही है।

ग्रेड पे और सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा

मनरेगा कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में लंबे समय से लंबित 'ग्रेड पे' का निर्धारण, एक ठोस 'एचआर पॉलिसी' का निर्माण और कर्मचारियों के लिए 'सामाजिक सुरक्षा' सुनिश्चित करना शामिल है। इन कर्मचारियों का तर्क है कि वे वर्षों से मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सुविधाओं और सेवा शर्तों के मामले में उन्हें लगातार अनदेखा किया जा रहा है। उनका कहना है कि अस्थाई सेवा और असुरक्षित भविष्य के कारण वे मानसिक और आर्थिक तनाव से गुजर रहे हैं, जिसे अब बर्दाश्त करना संभव नहीं है।

उग्र आंदोलन की चेतावनी से प्रशासन सतर्क : छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी संघ ने चेतावनी दी है कि यदि इस चरणबद्ध हड़ताल के बाद भी राज्य सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं करती है, तो वे आगामी दिनों में 'उग्र आंदोलन' का रास्ता अख्तियार करेंगे। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार को बातचीत के जरिए समाधान निकालना चाहिए, अन्यथा काम बंद होने से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी योजना का पूरा तंत्र ठप हो जाएगा। इस अल्टीमेटम के बाद से ही प्रशासनिक महकमे में हलचल तेज हो गई है और सरकार के स्तर पर इस स्थिति को संभालने के लिए विचार-विमर्श की संभावना जताई जा रही है।

ग्रामीण विकास कार्यों पर पड़ेगा सीधा असर : मनरेगा के तहत राज्य में बड़ी संख्या में गरीब परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। यदि 12 हजार से अधिक कर्मचारी काम पर नहीं लौटते हैं, तो इसका सीधा असर दैनिक मजदूरी भुगतान, नए कार्यों के आवंटन और चल रहे निर्माण कार्यों की निगरानी पर पड़ेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार से जुड़ी इस सबसे बड़ी योजना का पहिया थमने से आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल, सभी की निगाहें अब 2 जुलाई पर टिकी हैं कि क्या सरकार और कर्मचारी संघ के बीच किसी प्रकार का समझौता हो पाता है या फिर प्रदेश में एक लंबा गतिरोध देखने को मिलेगा।

18 वें जन्मदिन के तीन दिन बाद रेत में दफन मिली युवती की लाश,पोस्टमार्टम में हुए चौकाने वाले खुलासे...

महासमुंद,24 जून 2026। जिले के खल्लारी थाना क्षेत्र में 18 वर्षीय युवती की संदिग्ध मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। जन्मदिन की रात घर से लापता हुई युवती का शव तीन दिन बाद गांव के पास एक नाले की रेत में दफन मिला। प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आए तथ्यों ने मामले को और गंभीर बना दिया है। पुलिस अब हत्या और संभावित यौन अपराध दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। ग्राम पंचायत झारा के पास सोमवार दोपहर ग्रामीणों को नाले के किनारे रेत से दुर्गंध आती महसूस हुई। जब लोगों ने पास जाकर देखा तो रेत में दबा एक शव नजर आया। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। बाद में मृतका की पहचान 18 वर्षीय भारती टंडन के रूप में हुई, जो 19 जून की रात से लापता थी। शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवती के सिर पर गंभीर चोट मिलने की पुष्टि हुई है। डॉक्टरों के अनुसार सिर पर गहरा घाव था, जिससे खोपड़ी की हड्डी भी क्षतिग्रस्त पाई गई। इसके अलावा जांघों पर खरोंच के निशान मिले हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस दुष्कर्म की आशंका से भी इनकार नहीं कर रही है।

नारायणपुर में फिर गरमाया धर्मांतरण का मुद्दा,26 परिवारों को गांव से निकाला खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर

नारायणपुर,24 जून 2026। नारायणपुर जिले के भरंडा गांव में धर्मांतरण का विवाद एक बार फिर उग्र हो गया है। ईसाई धर्म अपनाने वाले 26 परिवारों को गांव से बाहर निकाल दिया गया है। ये परिवार अब गांव के बाहर पेड़ों की छांव में रहने को मजबूर हैं। अचानक हालात बिगड़ गए। ग्रामीणों ने इन परिवारों को गांव छोड़ने का फरमान सुना दिया। देखते ही देखते 26 परिवारों को अपना घर छोड़ना पड़ा। इस वक्त भरंडा गांव में भारी तनाव है। पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। यह कोई पहली घटना नहीं है। भरंडा गांव में दिसंबर 2025 से ही माहौल तनावपूर्ण है। विवादों का दौर रुक-रुककर चलता रहा, लेकिन 9 जून के बाद सब कुछ हाथ से निकल गया। उस दिन दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई थी। तब प्रशासन ने हस्तक्षेप करके मामला शांत कराया था। लेकिन दो दिन पहले स्थिति फिर बिगड़ गई। ग्रामीणों का साफ कहना है कि ये लोग अपनी मूल संस्कृति और परंपरा से दूर हो रहे हैं।

एलबी शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत : पेंशन पात्रता मामले में सेवा गणना पर पुनर्विचार का फैसला बरकरार

बिलासपुर,24 जून 2026। शिक्षक एलबी संवर्ग की पेंशन पात्रता से जुड़े महत्वपूर्ण मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को राहत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सरकार द्वारा दायर रिट अपील को खारिज करते हुए सिंगल बेंच के उस आदेश को यथावत रखा, जिसमें शिक्षकों की सेवा अवधि की गणना के मुद्दे पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया गया था। इस फैसले को राज्य के हजारों एलबी शिक्षकों के लिए अहम माना जा रहा है।

डिवीजन बेंच ने खारिज की सरकार की अपील : चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की रिट अपील को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि सिंगल बेंच द्वारा दिए गए निर्देश न्यायिक दायरे के भीतर थे और उनमें किसी प्रकार का न्यायिक अतिक्रमण नहीं था।

क्या है पूरा मामला? मामले में याचिकाकर्ता सहित अन्य शिक्षकों ने मांग की थी कि पेंशन पात्रता निर्धारित करते समय उनकी शिक्षाकर्मी के रूप में दी गई पूर्व सेवा को भी गणना में शामिल किया जाए। शिक्षकों का तर्क था कि उन्होंने वर्षों तक शिक्षाकर्मी के रूप में कार्य किया और बाद में उन्हें नियमित शासकीय सेवा में समाहित किया गया। वर्तमान व्यवस्था में सरकार शिक्षकों की सेवा अवधि की गणना केवल 1 जुलाई 2018 से कर रही है, जब उन्हें नियमित शासकीय सेवा में शामिल किया गया था। जबकि पेंशन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 10 वर्ष की शासकीय सेवा आवश्यक है। इस वजह से कई शिक्षक अपनी लंबी सेवा के बावजूद पेंशन पात्रता से वंचित हो रहे हैं।

हाईकोर्ट ने क्या कहा? अदालत ने स्पष्ट किया कि सिंगल बेंच ने सरकार को कोई नई नीति लागू करने का निर्देश नहीं दिया था। आदेश में केवल इस विषय पर पुनर्विचार करने और उचित निर्णय लेने की बात कही गई थी। डिवीजन बेंच के अनुसार यह निर्देश पूरी तरह न्यायिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह मुद्दा केवल कुछ शिक्षकों तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य के बड़े कर्मचारी वर्ग को प्रभावित करता है। इस विषय को लेकर लगातार विवाद और मुकदमे सामने आ रहे हैं। ऐसे में सरकार को एक स्पष्ट, तर्कसंगत और पारदर्शी नीति बनानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे विवादों की पुनरावृत्ति न हो।

बड़ी संख्या में शिक्षकों को मिल सकता है लाभ : अदालत के फैसले के बाद अब सरकार के स्तर पर पेंशन पात्रता और सेवा अवधि की गणना को लेकर नए सिरे से विचार किए जाने की संभावना बढ़ गई है। यदि इस दिशा में सकारात्मक निर्णय लिया जाता है, तो राज्य के बड़ी संख्या में शिक्षक इससे लाभान्वित हो सकते हैं।

वॉशिंग पाउडर की आड़ चल रही थी गुटखा फैक्टरी,पुलिस की रेड मशीनें-पैकिंग का सामान जब्त,गोदाम सील

दुर्ग-भिलाई,24 जून 2026। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के कचांदूर गांव में वॉशिंग पाउडर की पैकिंग की आड़ में अवैध रूप से चल रही जर्दा युक्त गुटखा बनाने की फैक्ट्री को पुलिस ने सील कर दिया है। पुलिस ने छापेमारी कर गुटखा निर्माण में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल, पैकिंग का सामान और मशीनें बरामद कीं। कार्रवाई के बाद फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। जांच में पता चला कि उत्तर प्रदेश निवासी आरोपी मोहम्मद सानू ने निरमा पाउडर की पैकिंग का काम बताकर 15-20 दिन पहले गोदाम किराए पर लिया था। कुछ समय बाद उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया। गोदाम मालिक ने उससे संपर्क करने की कई बार कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो सकी। परिसर में तैनात गार्ड ने भी मालिक को अंदर कुछ गड़बड़ी होने की आशंका जताई। इसी दौरान गोदाम में संदिग्ध गतिविधियां नजर आने लगीं, जिसके बाद मालिक ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और गोदाम मालिक की मौजूदगी में ताला खोलकर जांच शुरू की। पुलिस ने जांच के दौरान गोदाम के अंदर बड़ी मात्रा में जर्दा युक्त गुटखा बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल, पैकिंग सामग्री और मशीनें बरामद की गईं। मौके से मिक्सर मशीन, कटर मशीन समेत कई उपकरण जब्त किए हैं। इसके अलावा कई बोरियों में गुटखा बनाने का रॉ-मटेरियल भी मिला।

फायर सेफ्टी व्यवस्था पर हाई कोर्ट सख्त राज्य सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

बिलासपुर,24 जून 2026। छत्तीसगढ़ में आग लगने की बढ़ती घटनाओं और आपदा प्रबंधन व्यवस्था को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से विस्तृत जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने आधुनिक फायर ब्रिगेड वाहनों और उपकरणों की खरीद प्रक्रिया पर अद्यतन स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि केवल बजट आवंटित करना और टेंडर जारी करना पर्याप्त नहीं है। सरकार को यह भी बताना होगा कि खरीद प्रक्रिया किस चरण में है और संबंधित कार्यों के लिए वर्क ऑर्डर कब जारी किए गए हैं। राज्य अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग के निदेशक द्वारा दायर हलफनामे में बताया गया कि करीब 72.70 करोड़ रुपये की लागत से फायर टेंडर, वॉटर टेंडर, फोम टेंडर और मिनी-मिस्ट फायर वाहनों की खरीद की प्रक्रिया GeM पोर्टल के माध्यम से जारी है।

महिला कर्मचारियों को बड़ी राहत,संविदा और दैनिक वेतनभोगियों को भी मातृत्व अवकाश

बिलासपुर,24 जून 2026। बिलासपुर हाईकोर्ट ने कामकाजी महिलाओं के मातृत्व अधिकारों को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव वाला फैसला सुनाया है। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि मातृत्व अवकाश और इससे जुड़े वित्तीय लाभ प्राप्त करना केवल नियमित सरकारी कर्मचारियों का विशेषाधिकार नहीं है। अब से दैनिक वेतनभोगी, मस्टर रोल पर कार्यरत कर्मी, संविदा कर्मचारी और कॉलेजों में सेवाएं दे रहे अतिथि व्याख्याताओं को भी मातृत्व अवकाश का समान अधिकार प्राप्त होगा। यह निर्णय कार्यस्थल पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यह कानूनी लड़ाई रायपुर की शिल्पी शुक्ला द्वारा शुरू की गई थी, जो नवंबर 2022 से शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज में अतिथि व्याख्याता के पद पर कार्यरत हैं। गर्भावस्था के दौरान उन्हें 13 सितंबर 2025 से मातृत्व अवकाश की स्वीकृति मिली थी, जिसके बाद वे 20 मार्च 2026 को पुनः अपने कर्तव्य पर लौट आईं। अवकाश की अवधि समाप्त होने के बाद जब उन्होंने अपने देय वेतन और लाभों के लिए आवेदन किया, तो उच्च शिक्षा विभाग ने उनके दावे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वे एक नियमित कर्मचारी नहीं हैं। विभाग का तर्क था कि संविदा या अतिथि प्रकृति की नौकरी में इस तरह के वित्तीय लाभ का कोई प्रावधान नहीं है। विभागीय इनकार के बाद शिल्पी शुक्ला ने इस अन्याय को हाईकोर्ट में चुनौती दी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अपने पुराने तर्क दोहराते हुए कहा कि अतिथि व्याख्याता होने के कारण याचिकाकर्ता इन लाभों की पात्र नहीं हैं। इसके जवाब में याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि मातृत्व लाभ किसी महिला का मानवीय, मौलिक और कानूनी अधिकार है, जिसे केवल नौकरी की प्रकृति का हवाला देकर छीना नहीं जा सकता। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णयों का भी हवाला दिया गया, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि मातृत्व अवकाश का अधिकार कर्मचारी की सेवा श्रेणी या उसके पद की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)